# संगठन तथा आंदोलनात्मक कार्रवाइयों की रिपोर्ट

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

## तृतीय वार्षिक सम्मेलन

२१ से २५ मई, १९७५ / सन्मुखानंद हाल, बम्बई

सी०आई०टी०यू० की दूसरी कान्फ्रेंस के बाद से, इस कान्फ्रेंस में तै की गई नीतियों को आधार बनाकर हमारी यूनियनें रोजमर्रा के संघर्ष चलाने में व्यस्त रही हैं। कुछ संघर्षों का तो स्वयं हमने नेतृत्व किया है, जब कि उन कुछेक को हमने एकजुटता का समर्थन दिया है, जो दूसरे संगठनों के नेतृत्व में चलाए गए हैं। हमारे द्वारा चलाए गए संघर्षों की एक समीक्षा डेलीगेटों में प्रसारित की जा चुकी है यहां पर हम सी० आई० टी० यू० की दूसरी कांन्फ्रेंस के बाद से अबतक सी० आई० टी० यू० के कार्यों पर विचार करेंगे।

## वर्किंग कमेटी की मीटिंग (नई दिल्ली)

३ अक्तूबर से ५ अक्तूबर १९७३ तक, नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में छत्तीस सदस्य और पांच विशिष्टरूप से आमंत्रित किए गए लोग उपस्थित थे। सी०आई०टी०यू० के प्रेसीडेंट का० बी० टी० रणदिवे मीटिंग की अध्यक्षता की।

चूंकि यह मीटिंग चिली में तत्काल होकर चुकी प्रतिक्रांतिकारी सत्ता बदल के एकदम बाद हो रही थी इसलिए का० रणदिवे ने अपने भाषण में चिली में हुए इस घटना चक्र का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति और मेहनतकश वर्ग पर बढ़ रहे हमलों की भी समीक्षा की। का० पी० राममूर्ति के अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि किस तरह से मेहनतकश वर्ग के अधिकाधिक हिस्सों को एक साथ एकजुट करते हुए संयुक्त आंदोलन उभर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर दस कामरेडों ने बहस की।

राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद द्वारा नई दिल्ली में 'उत्पादकता और औद्योगिक संबंधों' विषय पर आयोजित एक सैमिनार के

बारे में का० पी० राममूर्ति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के प्रति अपनायी जाने वाली नीति पर बहस की गई जिसमें छः कामरेडों ने भाग लिया। सी०आई०टी०यू० के प्रतिनिधियों द्वारा सेमिनार में अपनाए गए रुख से आम तौर पर सहमत होते हुए भी, इस मीटिंग में यह तै किया गया कि सैमिनार द्वारा बनाए गए स्टीयरिंग ग्रुप से अपने नुमाइंदों को वापस बुला लिया जाए।

इस मीटिंग में, अखिल भारतीय प्लांटेशन वर्कर्स फैडरेशन के दफ्तर में आए कृषि वन्य और प्लांटेशन वर्कर्स के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन के नुमाइंदों के निरीक्षण कार्य पर भी रिपोर्ट सुनी गई।

इस मीटिंग में, एर्नाकुलम में हुई उद्योगानुसारी डेलीगेटों की रिपोर्टों और उन्हें लागू करने में सी०आई०टी०यू० सेन्टरों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी विचार किया। मीटिंग में उद्योगानुसारी संयोजन और सी०आई०टी०यू० यूनियनों के कार्यों के दिशा निर्देश के लिए कुछ संगठनात्मक फैसले भी लिए गए।

मीटिंग में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर कुछ प्रस्ताव भी स्वीकृत किए जिनमें भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव की कमी; बढ़ते हुए दमन चक्र; हरिजनों पर अत्याचार, लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के संघर्ष और तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ लड़ रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ एकजुटता इत्यादि के प्रस्ताव प्रमुख हैं।

## जनरल कांउसिल की मीटिंग (विशाखापतनम्)

४ से लेकर ७ अप्रेल १९७४ तक विशाखापतनम् में जनरल कांउसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता का० बी० टी० रणदिवे ने की। इसमें १४९ सदस्य और विशिष्ट आमंत्रित लोग शामिल हुए। इस शहर में सी०आई०टी०यू० की यूनियनों के कमजोर होने के बावजूद, शहर की बहुत सी मित्र-यूनियनों ने इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए उल्लेखनीय सहायता दी। का० बी० टी० रणदिवे का लिखित भाषण और महासचिव की रिपोर्ट दोनों ने ही, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना-विकास और मजदूरों के सामने आ रही समस्याओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला। मजदूरों के बीच उभर रहे संयुक्त संघर्षों की भी समीक्षा प्रस्तुत की गई।

महासचिव की रिपोर्ट पर हुई बहस में इकत्तीस कामरेडों ने भाग लिया। उत्पादकता और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् में अपनाए गए सी०आई०टी०यू० के रुख पर विस्तार से विचार हुआ जिसमें पच्चीस सदस्यों ने हिस्सा लिया। एक नीतिगत वक्तव्य स्वीकृत किया गया जिसमें इस उत्पादकता आन्दोलन के तमाम पहलुओं के खिलाफ सी०आई०टी०यू० यूनियनों को संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया गया था। अनुशासन की आचारसंहिता के बारे में, तथा ई०एस०आई० योजना के प्लांटेशन, खान और अन्य प्रतिष्ठानों में विस्तार के बारे में सी०आई०टी०यू० का रुख क्या होना चाहिए, इस पर भी विचार किया गया।

सी०आई०टी०यू० के प्रेसीडेंट का० बी० टी० रणदिवे ने वियतनाम के दौरे के बारे में बताया और अमेरिकी हमले के खिलाफ वियतनामी जनता के बहादुराना संघर्ष का चित्रण किया। मजदूर वर्ग के सामने आ रहे विभिन्न सामयिक मसलों और समस्याओं के बारे में विभिन्न प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् १९७३ के वर्ष के लिए एकाउन्ट्स के औडिटेड स्टेटमेंट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। मीटिंग में कामरेड ए० पी० चटर्जी, प्रकाश घोष, विश्वनाथ दासगुप्ता, विमला रणदिवे और सुखमय पाल को जनरल कांउसिल की सदस्यता के लिए मनोनीत करना तै किया गया।

प्लांटेशनों, सड़क यातायात, बंदरगाह और गोदी इंजीनियरिंग, बिजली, कागज और बीड़ी उद्योगों में सी०आई०टी०यू० यूनियनों के सह-संयोजन के लिए इन उद्योगों के अनुसार मीटिंगें की गई।

७ अप्रैल को एक जनसभा की गई जिसमें कामरेड एन० प्रसाद राव द्वारा अध्यक्षता की गई और जिसे कामरेड बी० टी० रणदिवे, पी० राममूर्ति, और का० ज्योति बसु द्वारा संबोधित किया गया।

इस जनरल कांउसिल से पहिले ४ अप्रैल को वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई थी जिसमें जनरल काउंसिल की मीटिंग के समक्ष आने वाले मसलों पर सोच विचार किया था।

## शिवपुर वर्किंग कमेटी मीटिंग

११ से १४ दिसम्बर (१९७४) तक शिवपुर (हावड़ा) में हुई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ४३ सदस्य और विशिष्ट आमंत्रित लोग उपस्थित हुए। अखिल भारतीय रेल हड़ताल के पश्चात्

वह पहिली मीटिंग थी और अध्यक्षीय भाषण एवं महासचिव की रिपोर्ट दोनों का ही एक बड़ा अंश इस हड़ताल पर केन्द्रित किया गया। इस मीटिंग की कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए रेलवे आंदोलन के चार प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया था। चूंकि यह मीटिंग विभिन्न राज्यों, मंडलों और इलाकों के स्तर पर वेतनजाम विरोधी कन्वेंशनों तथा २८ अगस्त १९७४ को आयोजित नई दिल्ली के वेतनजाम विरोधी मेहनतकश जनता के अखिल भारतीय कन्वेंशन इत्यादि, के बाद में हो रही थी इसलिए, वेतन-जाम के खिलाफ दूसरी सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के सहयोग से समूचे देश के स्तर पर एक दिन की हड़ताल करने की संभावनाओं पर भी इस मीटिंग में विचार किया गया।

अध्यक्ष के लिखित भाषण और महासचिव की रिपोर्ट के अलावा वर्तमान स्थिति के विकास के ऊपर भी एक टिप्पणी सदस्यों के बीच प्रसारित की गई।

मीटिंग में, विभिन्न उद्योगों में उद्योगानुसार कार्यपद्धति पर विचार किया गया और संबंधित सी०आई०टी०यू० यूनियनों की विभिन्न कार्रवाइयों को सह-संयोजित करने के लिए उचित संभावनात्मक फैसले लिए गए। गोदी और बंदरगाह, सड़क यातायात, प्लांटेशन, रेयन और रबर और टायर उद्योगों में कार्यरत कामरेडों की उद्योगानुसार मीटिंगें दिसंबर १९७४ में हुईं।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं मजदूरों के सामने आती हुई विभिन्न समस्याओं पर प्रस्ताव पारित करने के बाद, मीटिंग ने सी०आई०टी०यू० की तीसरी कान्फ्रेंस को बंबई में मई १९७५ में करने के, सी०आई०टी०यू० महाराष्ट्र राज्य के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया।

मीटिंग के पश्चात् १४ दिसंबर को हावड़ा जूट मिल मैदान में एक बड़ी रैली की गई जिसे कामरेड बी०टी० रणदिवे, ज्योतिबसु, पी० राममूर्ति और हरिसाधन मित्रा द्वारा संबोधित किया गया।

सैक्रेटरिएट समय समय पर दो वर्किंग कमेटियों के दो सैशनों के बीच बीच में आने वाले नीति संबंधी मसलों पर विचार करता रहता है। दूसरी कान्फ्रेंस के बाद से अब तक, ऐसी १० मीटिंगें हुई हैं जिनमें फौरी मसलों के संदर्भ में नीतियों पर विचार विमर्श किया गया है। इन मीटिंगों में सिर्फ वे ही सदस्य उपस्थित हो

सके जो कलकत्ता में उपलब्ध रहे। व्यापक सलाह मशविरे के लिए कामरेड कृष्ण पाद घोष और कामरेड बिरेन राय को भी मीटिंगें अटैन्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया। एक मौके पर बहत्तर पदाधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई गई जिसमें उपलब्ध हो सकने वाले सदस्यों को भी आमन्त्रित किया गया था। अपरिहार्य परेशानियों के फलस्वरूप, जब कभी सेक्रेटरिएट की मीटिंग कर पाना संभव नहीं हुआ वहां सभी महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय लेने से पहिले उपलब्ध सदस्यों से सलाह मशविरा लिया गया।

## राज्यों में कान्फ्रेंस

दूसरी कान्फ्रेंस के बाद अधिकांश राज्यों में तीसरी कान्फ्रेंस की तैयारी के रूप में राज्य स्तर की कान्फ्रेंसें की गई हैं। इन कान्फ्रेंसों की एक संक्षिप्त समीक्षा यहां नीचे दी जा रही है:—

**तमिलनाडु**

तमिलनाडु राज्य कमेटी की दूसरी कान्फ्रेंस २० से २३ दिसंबर १९७३ तक मद्रास में हुई। इस कान्फ्रेंस का उद्घाटन सी०आई०टी०यू० के महासचिव कामरेड पी० राममूर्त्ति ने किया और इसकी अध्यक्षता कामरेड के० रामानी द्वारा की गई। इस कान्फ्रेंस में १४९ यूनियनों और दूसरे भाई-चारे वाले संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले ४३३ डैलीगेटों ने भाग लिया। इसमें कामरेड उमानाथ ने एक आम रिपोर्ट पेश की, साथ ही सह-सचिव कामरेड ए० नल्लाशिवन ने कार्रवाहियों पर रिपोर्ट पेश की। इन रिपोर्टों पर हुए विचार विमर्श में ३८ डैलीगेटों ने भाग लिया। इन बहसों के बाद में रिपोर्टें पारित हुई। कान्फ्रेंस में कन्याकुमारी जिले के हड़ताली यातायात मजदूरों एवं विक्रम सिंह पुरम के कपड़ा मजदूरों के समर्थन में १० जनवरी १९७४ को एकजुटता दिवस मनाने का आह्वान किया। अंत में लगभग ५०,००० मजदूरों के बड़े प्रदर्शन एवं एक लाख मजदूरों की एक जन सभा के साथ यह कान्फ्रेंस समाप्त हुई जिसमें कामरेड पी० राममूर्ति, कामरेड आर० उमानाथ, कामरेड वी०पी० चिंतन, कामरेड कुचलर, कामरेड कृष्ण-मूर्ति ने भाषण दिये। कान्फ्रेंस ने ४० सदस्यों की, एक नई कमेटी का चुनाव किया जिसमें कामरेड के० रामानी को अध्यक्ष और कामरेड आर० उमानाथ को महासचिव चुना गया।

**मध्य प्रदेश**

दूसरी कान्फ्रेंस से पहिले इस राज्य में कोई भी राज्य समिति नहीं बनाई जा सकी। सी०आई०टी०यू० सैंटर ने २५ से २७ दिसम्बर १९७३ तक भिलाई में प्रथम कन्वेंशन बुलाया। कामरेड बी० टी० रणदिवे, जिन्हें इस कन्वेंशन का उद्घाटन करना था, लोकोरनिंग स्टाफ की हड़ताल के फलस्वरूप रेलवे यातायात की गड़बड़ी के कारण, वहाँ नहीं पहुंच सके। इसलिए सी०आई०टी०यू० के उपाध्यक्ष कामरेड मोहम्मद इस्माइल ने इस कन्वेंशन का उद्घाटन किया। कामरेड एम० के० पन्धे (सी०आई०टी०यू० के सचिव) ने राज्य के स्तर पर चलने वाली सी०आई०टी०यू० की कार्रवाइयों की एक आम रिपोर्ट पेश की। २० से ज्यादा डेलीगेटों ने बहस में हिस्सा लिया। कन्वेंशन ने कामरेड एस० कुमार के संयोजन में एक संयोजन समिति का गठन किया। कन्वेंशन के आखिर में एक जनसभा हुई जिसे कामरेड मोहम्मद इस्माइल, एस० के० पन्धे, मोती लाल शर्मा, विमला रणदिवे और अन्य कामरेडों के द्वारा संबोधित किया गया।

**दिल्ली**

सी०आई०टी०यू० की दिल्ली राज्य कमेटी की दूसरी कान्फ्रेंस दिल्ली में २ और ३ जनवरी १९७४ को करमपुरा में हुई। सी० आई०टी०यू० के अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने इसका उद्घाटन किया और इसकी कार्रवाइयों का दिशा-निर्देश किया। इसमें टैक्सटाइल, इंजीनियरिंग, खाद्य और पेय, भवन और निर्माण और व्यापारिक संस्थानों में ११,३९७ की सदस्यता वाली १३ यूनियनों के डैलीगेटों ने भाग लिया। कामरेड टी० एम० नागराजन ने प्रथम कान्फ्रेंस के बाद से लेकर उस तिथि तक की एक रिपोर्ट पेश की जिसे विचार विमर्श के बाद स्वीकृत कर लिया गया। कान्फ्रेंस ने एक नई राज्य कमेटी का चुनाव भी किया जिसमें कामरेड टी० एम० नागराजन को अध्यक्ष और कामरेड घनश्याम शरण सिन्हा को महासचिव चुना गया।

विशाखापतनम की जनरल कांउसिल के फैसले के अनुसार दिल्ली हरियाणा और पश्चिमी यू० पी० के लिए एक रीजनल कमेटी का गठन किया गया। इस रीजनल कमेटी की एक कान्फ्रेंस २६ से

२७ अप्रेल १९७५ तक नई दिल्ली में हुई। इस कान्फ्रेंस का उद्घाटन सी०आई०टी०यू० अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने किया (इस रिपोर्ट के लिखते वक़्त तक केन्द्रीय कार्यालय को, नई दिल्ली कान्फ्रेंस की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी)।

**राजस्थान**

सी०आई०टी०यू० यूनियनों के पदाधिकारियों का एक विशेष कन्वेशन ३० और ३१ दिसम्बर १९७३ को बीकानेर में हुआ। सी०आई०टी०यू० अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने इस कन्वेंशन का उद्घाटन किया और इस की अध्यक्षता सी०आई०टी०यू० की राजस्थान राज्य कमेटी के अध्यक्ष कामरेड मोहन पुनमिया ने की। कामरेड डी० डी० शिराली ने राज्य स्तर पर सी०आई०टी० यू० यूनियनों द्वारा चलाए गए संघर्षों की समीक्षा की। कन्वेंशन ने मूल्यवृद्धि बेरोजगारी इत्यादि के खिलाफ समूचे राज्य स्तर पर प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए सभी मजदूरों का आह्वान किया और ई० एस० आई० के विरुद्ध सभी मजदूरों की समस्याओं को बुलंद करने के लिए २२ जनवरी १९७४ को एक विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया। इस कन्वेंशन ने १४ फरवरी १९७४ को राज्य-व्यापी स्तर पर इंजीनियरिंग मजदूरों की हड़ताल करने का फैसला लिया।

राज्य स्तर की तीसरी कान्फ्रेंस १४ से १६ फरवरी १९७५ तक भरतपुर में हुई जिसमें राज्य में सी०आई०टी०यू० का उल्लेखनीय विकास देखने में आया। सी०आई०टी०यू० की आधार-शिला इस कान्फ्रेंस में वैसे तो ८५५९ की सदस्यता वाली २९ यूनियनों ने ही भाग लिया लेकिन इस कान्फ्रेंस ने वास्तव में २२,५०० की सदस्यता वाली ८० यूनियनों की ताकत का प्रतिबिंबन किया। इसमें ३४५ डैलीगेटों और १४३ प्रेक्षकों ने हिस्सा लिया जिनमें २० औरतें थीं। डैलीगेटों में से अधिकांश (बहुमत) की उम्र ३० वर्ष से भी कम थी। सिमकों के तीन शहीद कामरेडों को श्रद्धांजलि देने के बाद, जो अगस्त १९७४ में पुलिस की गोली से मारे गए थे, सी०आई०टी०यू० अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने कान्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कामरेड मोहन पुनमिया ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया और कामरेड डी० डी० शिराली ने एक आम रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के ऊपर हुए विचार-विमर्श में लग-

भग ५२ डैलीगेटों ने हिस्सा लिया। कान्फ्रेंस ने, छात्रों, किसानों, प्रेस संवाददाताओं और दूसरे तबकों पर हो रहे दमन के खिलाफ तथा मेहनतकश वर्ग की कुछ मांगों के लिए **राजस्थान बंद** आयोजित करने का फैसला लिया। इसमें अगली मई तक एक लाख रुपया एकत्रित करने का फैसला भी लिया जिससे अदालती केसों में फंसे मजदूरों की रक्षा की जा सके और दमन-उत्पीड़न का शिकार हुए मजदूरों के परिवारों को राहत दी जा सके। कान्फ्रेंस ने कोटा के उन ७ साथियों को भी बचाने का फैसला लिया जिन्हें अदालत ने आजीवन कारावास का दण्ड दिया था। कान्फ्रेंस ने यूनियन पर लेवी दर को बढ़ाने का भी फ़ैसला किया जिससे कि राज्य कमेटी के बढ़ते हुए खर्चे को पूरा किया जा सके। कान्फ्रेंस ने एक नई राज्य कमेटी का गठन किया जिसका कामरेड मोहन पुनमिया को अध्यक्ष चुना गया।

**केरल**

केरल राज्य कमेटी की दूसरी कान्फ्रेंस त्रिचूर में २० सितम्बर १९७४ को हुई १, ८१, ९११ की कुल सदस्यता रखने वाली ३४३ यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले ८५९ डैलीगेटों की यह कान्फ्रेंस १८ सितम्बर १९७४ को वेतनज़ाम के खिलाफ एक काम-याब केरल बंद के एकदम बाद हो रही थी। सी०आई०टी०यू० के अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने कांन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और राज्य कमेटी के अध्यक्ष कामरेड सी० कन्नन द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। राज्य के महासचिव कामरेड ई० बालनंदन ने १९७० में हुई प्रथम कांन्फ्रेंस के बाद से अब तक हुई गतिविधियों की एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर ३० से अधिक कामरेडों ने बहस की और उसके पश्चात उसे सर्व सम्मति से स्वीकृत किया। पश्चिम बंगाल सी०आई०टी०यू० की राज्य कमेटी की ओर से कामरेड मोहम्मद इस्माइल ने कांन्फ्रेंस को बधाइयाँ दीं और कामरेड एम० के० पन्धे ने कुछेक संगठनात्मक समस्याओं पर बोला। कांन्फ्रेंस को कामरेड ई० एम० एस० नंबूदरीपाद, कामरेड ई० के० नयवार और अन्य कामरेडों ने भी बधाइयाँ दी। इस कांन्फ्रेंस के दौरान 'विश्व के आर्थिक संकट' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें अन्य कामरेडों के अतिरिक्त कामरेड बी० टी० रणदिवे ने भी शिरकत की। कान्फ्रेंस ने १८३ सदस्यों की जनरल कांउसिल और ३१ सदस्यों की कार्यकारिणी कमेटी भी गठित की जिसके अध्यक्ष

कामरेड सी० कन्नन और महासचिव कामरेड ई० बालनंदन बनाए गए। कान्फ्रेंस के आखिर में एक भव्य जुलूस निकला, शहर की मुख्य सड़कों पर हजारों हजार मजदूरों ने परेड निकाली जो बाद में एक लाख से भी ज्यादा लोगों की एक जनसभा में बदल गई, जिसे कामरेड बी० टी० रणदिवे, कामरेड ई० एम० एस० नंबूदिरीपाद, कामरेड बी० टी०, कामरेड सी० कन्नन और कामरेड एस० बालनंदन ने संबोधित किया।

**महाराष्ट्र**

सी०आई०टी०यू० की महाराष्ट्र राज्य कमेटी की दूसरी कान्फ्रेंस बंबई में २० से २३ दिसंबर १९७४ तक हुई। ५५० से ज्यादह डैलीगेटों और प्रेक्षकों ने कान्फ्रेंस में भाग लिया। सी०आई०टी०यू० के अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने कान्फ्रेंस का उद्घाटन किया। सी०आई०टी०यू० की राज्य कमेटी के महासचिव कामरेड पी० के० कुरणे ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में प्रथम कान्फ्रेंस के बाद राज्य में हुई सी०आई०टी०यू० की गतिविधियों की समीक्षा प्रस्तुत की। रिपोर्ट के ऊपर हुई बहस में लगभग ६० डैलीगेटों ने भाग लिया और बाद में वह सर्व सम्मति से स्वीकृत हो गई। कान्फ्रेंस ने पिछले चार सालों में सी०आई०टी०यू० की सदस्यता के तीन गुने (लगभग १९,००० से ५७,०००) हो जाने को स्पष्ट रूप से दर्शाया। कान्फ्रेंस ने ४२ सदस्यों की एक राज्य कमेटी का गठन किया और क़ामरेड एस० बाई० कोल्हारकर को अध्यक्ष तथा कामरेड पी० के० कुरणे को महासचिव के रूप में चुना।

कान्फ्रेंस के बाद १०,००० से भी ज्यादा मजदूरों की एक जन-सभा हुई जिसमें कामरेड बी० टी० रणदिवे, कामरेड पी० राममूर्ति तथा अन्य कामरेडों ने भाषण दिए।

**उड़ीसा**

सी०आई०टी०यू० यूनियनों की प्रथम राज्य कान्फ्रेंस राउरकेला में १७ से १९ जनवरी १९७५ तक हुई। कुछ ही महीनों पहिले राज्य में सी०आई०टी०यू० की गतिविधियां संयोजित करने के लिए एक अस्थायी राज्य कमेटी बनाई गई थी। सी०आई०टी०यू० के अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने कान्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस कान्फ्रेंस में खानों, इस्पात, इंजीनियरिंग, यातायात और अन्य उद्योगों में काम करने वाले ८ जिलों के डैलीगेटों ने भाग

लिया। कामरेड शिवाजी पटनायक ने (जो तैयारी समिति के संयोजक थे), राज्य में सी०आई०टी०यू० की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। कान्फ्रेंस ने २५ सदस्यों की एक राज्य समिति चुनी और कामरेड अजेय राउत को उसका सचिव बनाया। इस काफ्रेंन्स के खुले अधिवेशन में पांच हजार मजदूरों ने भाग लिया जिसे दूसरे साथियों के अलावा कामरेड बी० टी० रणदिवे, समर मुखर्जी, और शिवाजी पटनायक के द्वारा संबोधित किया गया।

**पश्चिम बंगाल**

सी०आई०टी०यू० की राज्य कमेटी की दूसरी कान्फ्रेंस उत्तरी बंगाल माल बाजार में २५ से २८ दिसंबर (१९७४) तक हुई। इस कान्फ्रेंस की अध्यक्षता राज्य के सी०आई०टी०यू० अध्यक्ष कामरेड मोहम्मद इस्माइल ने की और इसका उद्घाटन कामरेड बी० टी० रणदिवे ने किया। राज्य में जारी आतंक राज के बावजूद इस कान्फ्रेंस में १००० से अधिक डैलीगेटों ने भाग लिया। राज्य की सी०आई०टी०यू० के महासचिव ने एक आम रिपोर्ट पेश की जिसके ऊपर हुई बहस में ५० डैलीगेटों ने भाग लिया। कामरेड बी० एस० बोस द्वारा कान्फ्रेंस में पेश की गई। संगठनात्मक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में संबद्ध यूनियनों की जो संख्या सन् १९७० में ९०० थी, १९७४ तक आते आते ११२० तक पहुंच गई। सदस्यता की संख्या भी इसी दौरान ४ लाख ७० हजार से बढ़कर ५ लाख हो गई। कान्फ्रेंस ने पश्चिम बंगाल के मजदूरवर्ग से वेतनजाम, ऊंचे दाम, बेरोजगारी इत्यादि के खिलाफ राज्यव्यापी स्तर पर एक दिन की आम हड़ताल करने का आह्वान किया। राज्य सी०आई०टी०यू० के उप-प्रधान कामरेड ज्योति बसु ने कान्फ्रेंस की कार्रवाइयों का निष्कर्ष दिया। कान्फ्रेंस ने एक नई जनरल काउंसिल और राज्य कमेटी बनाई। कामरेड मोहम्मद इस्माइल को अध्यक्ष तथा कामरेड मनोरंजन राय को महासचिव चुना गया। कान्फ्रेंस की समाप्ति के अवसर पर एक लाख की जन सभा हुई जिसे कामरेड बी० टी० रणदिवे, ज्योति बसु, मोहम्मद इस्माइल, मनोरंजन राय, सुहृद मल्लिक चौधरी, रतनलाल ब्राह्मण, और परिमल मिश्र के द्वारा संबोधित किया गया।

**आसाम**

सी०आई०टी०यू० की आसाम राज्य कमेटी की दूसरी कान्फ्रेंस १ से ३ फरवरी १९७५ तक ढुबरी में हुई। इसकी अध्यक्षता

कामरेड डी० पी० बरुआ ने की। इसमें ७३ डैलोगेट और ४३ प्रेक्षकों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल के महासचिव मनोरंजन राय ने कान्फ्रेंस का उद्घाटन किया और सी०आई०टी०यू० के उप-प्रधान कामरेड ज्योति बसु ने डैलीगेटों को बधाइयाँ दीं। आसाम राज्य कमेटी के सचिव कामरेड अमल घोष दस्तीदार ने सी०आई० टी०यू० की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट पेश की जो विचार विमर्श के बाद स्वीकार की गई। 'ट्रेड यूनियन आन्दोलन के काम और समस्याएं' विषय पर कान्फ्रेंस के आखिरी दिन एक सैमिनार भी हुआ जिसमें १५० ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं ने हिस्सा लिया। कामरेड ज्योति बसु इस सैमिनार के प्रमुख वक्ता थे। कान्फ्रेंस के खचाखच भरे खुले अधिवेशन में संसद सदस्य कामरेड नूरुल हुदा ने अध्यक्षता की और उसे कामरेड ज्योति बसु एवं कामरेड मनोरंजन राय द्वारा संबोधित किया गया। कांग्रेस ने कामरेड एस० हज़ारिका को अध्यक्ष और कामरेड अमल घोष दस्तीदार को महासचिव के रूप में चुना।

**गुजरात**

गुजरात में आंदोलन की कमजोरी के कारण किसी भी समिति का गठन कर पाना संभव नहीं था। दिसम्बर, १९७३ के अंतिम सप्ताह में अहमदाबाद में एक कन्वेंशन आयोजित की गई जिसका निर्देशन सी०आई०टी०यू० के उपाध्यक्ष कामरेड ज्योति बसु ने किया। कन्वेंशन ने एक राज्य समिति का चुनाव किया जिसमें कामरेड महेंडल को अध्यक्ष के रूप में एवं कामरेड चन्दूभाई पटेल को महामंत्री के रूप में चुना गया। गुजरात आंदोलन के दौरान अधिकांश सी०आई०टी०यू० नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय के लिए सींखचों के अंदर रखा।

**पंजाब और हिमाचल प्रदेश**

सी०आई०टी०यू० की पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य समितियों की दूसरी कांफ्रेंस दिनाँक २९-३० सितम्बर '१९७३ को बटाला में हुई, जिसमें ८००० सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली २३ यूनियनों के ७५ प्रतिनिधियों एवं मित्र संगठनों से २५ भ्रातृ-प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सी०आई०टी०यू० के महामंत्री कामरेड पी० राममूर्ति ने इसका उद्घादन किया। महामंत्री, कामरेड हरिसिंह कंग ने विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई रिपोर्ट प्रस्तुत की। कांफ्रेंस के तुरंत बाद राज्य समिति निष्क्रिय हो गई और बाद में मुख्यकेन्द्र

लुधियाना से जलन्धर स्थानान्तरित कर दिया गया। राज्य समिति द्वारा कामरेड जगजीत सिंह लायलपुरी को नए महामंत्री के रूप में चुना गया। राज्य की तीसरी कान्फ्रेंस दिनांक २५ और २६ अप्रैल, १९७५ के लिए निर्धारित की गई थी, किन्तु इस रिपोर्ट को लिखते समय तक केन्द्र को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

**गोआ**

गोआ राज्य समिति की दूसरी कान्फ्रेंस दिनांक १६ से १८ मई १९७५ के लिए निर्धारित की हुई है। इसका उद्घाटन कामरेड ज्योति बसु करेंगे।

बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विविध कारणों से कोई राज्य कान्फ्रेंस नहीं हो सकी है। अखिल भारतीय कान्फ्रेंस के बाद उन्हें आयोजित किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

## उद्योगानुसार सह-संयोजन की समस्याएं

मजदूरों की चेतना बढ़ने के साथ-साथ, स्थानीय संघर्ष क्रमशः रीजन व्यापी या उद्योग-व्यापी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। पिछले दिनों में यूनियनें कुछ ऐसी मांगें उठाती रही हैं जिन्हें सिर्फ अखिल भारतीय पैमाने के दबाव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। पब्लिक सैक्टर के कुछ उद्योग-प्रतिष्ठान देश के विभिन्न इलाकों में अपनी यूनिटें फैलाए हुए हैं इसलिये काम की स्थितियों में एक समानता की मांग, संबंधित सभी मजदूरों को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर देती है। विदेशी इजारेदारों में से कुछ की ब्रांचे देश के विभिन्न इलाकों में फैली हैं, और इन ब्रांचों में काम करने वाली यूनियनें आम मांगों को लेकर संघर्ष छेड़ने के लिए प्रायः साथ साथ आती रही हैं। विभिन्न केन्द्रीय संगठनों से संबद्ध विभिन्न स्थानीय यूनियनों के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिये संघर्ष को इस प्रकार एकजुट होकर चलाने के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन प्रवृतियों को प्रोत्साहित करने के लिए सी० आई० टी० यू० को हर संभव कदम उठाना होगा जिससे कि भविष्य में देश व्यापी वर्ग संघर्ष मजबूत हो सकें।

इसके अलावे, बड़े उद्योगों के अंदर व्यापक आधार वाले उद्योगानुसारी संघर्षों के निर्माण के लिए कुछ उद्योगों में सी० आई० टी० यू० की अपनी गतिविधियों के सह संयोजन का सवाल महत्वपूर्ण हो उठता है। सी० आई० टी० यू० सैन्टरों को इस समस्या पर ज्यादा-से ज्यादा ध्यान देना होगा।

पिछले दो वर्षों में अन्य बहुत सी व्यस्तताओं के बावजूद हमें कुछ उद्योगों के अंतर्गत अपने काम को प्राथमिकता देनी पड़ी है। सी० आई०टी०यू० की अगुआ संस्थाओं की मीटिंग के दौरान, इस काम से संबंधित सवालों पर, उचित संगठनात्मक फैसलों के लिए काफी विस्तार से विचार भी करना पड़ा है। इस संदर्भ में की गई गतिविधियों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट यहां दी जा रही है :-

**(१) सड़क यातायात उद्योग**

इस उद्योग से संबद्ध दूसरी कान्फ्रेंस में शामिल होने वाले डैलीगेटों की एक मीटिंग एर्नाकुलम में हुई जिसमें इस उद्योग की गतिविधियों को सह संयोजित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने हेतु एक कन्वेंशन बुलाने का फैसला लिया गया। दिल्ली वर्किंग कमेटी की मीटिंग में विचार करने के पश्चात् २५-२७ मई १९७४ को कलकत्ता में एक कन्वेंशन बुलाने का फ़ैसला दिया गया, किंतु रेल हड़ताल को देखते हुए इसे २८-३० जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया। इस उद्योग की यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक ८ अप्रैल १९७४ को आल इण्डिया कन्वेंशन की तैयारियों का ब्योरा तै करने के लिए विशाखापत्तनम् में की गई। सी०आई० टी०यू० के अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने इस कन्वेंशन का उद्घाटन किया और जिसमें पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के डैलीगेटों ने हिस्सा लिया। सी०आई० टी०यू० से बाहर की भी कुछ यूनियनों ने इस कन्वेंशन में हिस्सेदारी की। तामिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, और राजस्थान अपने डैलीगेट नहीं भेज सके। कन्वेंशन में एक अखिल भारतीय सड़क यातायात मजदूर फैडरेशन के निर्माण का फैसला किया गया। कन्वेंशन ने एक कार्यकारी कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष कामरेड वी० विश्वनाथ मेनन एवं महासचिव कामरेड सुजीत दास को बनाया गया। यह भी तै किया गया कि इस नए संगठन का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में रहेगा। कन्वेंशन में एक मांग पत्र भी स्वीकृत किया गया और इन मांगों को लोक प्रिय बनाने के लिए सितम्बर १९७४ के आखिर में सप्ताह मनाने का भी फैसला किया गया। इस फैडरेशन के पदाधिकारियों की एक वृहत्तर मीटिंग फैडरेशन के संविधान को अंतिम रूप देने के लिए कलकत्ता में १४ दिसंबर' १९७४ को हुई। सी०आई० टी०यू० सैंटर की ओर से सी०आई०टी०यू० के महासचिव कामरेड पी० राममूर्ति ने इस मीटिंग में भाग लिया। अक्तूबर १९७४ मास

में तमिलनाडु में इस उद्योग से संबंधित एक राज्य व्यापी कन्वेंशन हुआ। नवंबर १९७४ में आंध्र प्रदेश राज सड़क यातायात मजदूर फैडरेशन का कन्वेंशन हुआ। उड़ीसा में भी एक ऐसा ही कन्वेंशन हुआ। फिर भी, अभी फैडरेशन एक काम करने वाला केन्द्र बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है और केन्द्र एवं यूनिटों के मध्य नियमित संपर्क अभी बहुत मुकम्मिल नहीं हो पाए हैं। इस तीसरी कान्फ्रेंस के अवसर पर बंबई में ही इस फैडरेशन की कार्यकारी कमेटी की भी एक मीटिंग होने जा रही है।

## (२) प्लांटेशन उद्योग

१९७२ में बने अखिल भारतीय प्लांटेशन मजदूरों में फैडरेशन की कार्यकारी कमेटी की मीटिंग सी०आई०टी०यू० की दूसरी कान्फ्रेंस के अवसर पर हुई थी और वहां एक संविधान स्वीकृत किया गया था। इस फैडरेशन ने सितंम्बर १९७३ में कृषि वन्य और प्लांटेशन मजदूरों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के (डब्ल्यू०एफ०टी०यू०) के साथ संबद्धता (एफिलिएशन) प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के एक प्रतिनिधि ने फैडरेशन के कार्यालय में २५ सितंबर १९७३ को दौरा भी किया। इस फैडरेशन ने प्लांटेशन लेबर (संशोधन) बिल पर बनी संसद की संयुक्त समिति को एक मैमोरंडम भी दिया। इस कमेटी के आने पर स्थानीय यूनियनें उसके सामने भी गईं। इसके अलावे, ७ जुलाई १९७४ को मैमोरंडम के ब्योरों को समझने के लिए कमेटी के सामने जुबानी सुबूत भी प्रस्तुत किए गए। विशाखापत्तनम् में ८ अप्रैल १९७४ को हुई कार्यकारी कमेटी में, फैडरेशन ने २५ से ३१ मई तक एक मांग सप्ताह मनाने का फैसला किया जिससे कि प्लांटेशनों के बंद हो जाने और मजदूरों के भारी तादाद में बेकार हो जाने की समस्याओं को सामने लाया जा सके। इस मीटिंग में प्लांटेशन मजदूरों के दो लाख दस्तखत कराके अगस्त में संसद के सामने प्रस्तुत करने का भी फैसला किया गया। मांग सप्ताह, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, केरल, कर्नाटक में मनाया गया, किंतु यूनियनों ने मांगों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना पूरा जोर नहीं लगाया। दस्तखत अभियान में भी कुछ कम हौसला ही दिखाया गया और २१ अगस्त १९७४ को संसद में जमा करने के दिन तक कुल ४०,००० दस्तखत ही जुट पाए जिन्हें फैडरेशन के उप-अध्यक्ष संसद सदस्य कामरेड बीरेन दत्त ने जमा किया। फैडरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल बंद बागानों

को पुनः खुलवाने की मांग पर जोर देने के लिए केन्द्रीय व्यापार और श्रम मंत्री से मिला।

फैडरेशन की कार्यकारी कमेटी के पूर्व निर्णय के अनुसार ही, मद्रास में १५ अप्रैल १९७४ को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा आयोजित एक मीटिंग में कामरेड आर० उमानाथ ने भाग लिया जिसमें एशियाई प्लांटेशन मजदूर यूनियन के गठन पर विचार होना था। सी०आई०टी०यू० के प्रतिनिधि के अलावा इस मीटिंग में श्री लंका से दो प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के महासचिव ने भाग लिया। इस मीटिंग में एटक के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। इस मीटिंग में आई०टी०एफ० यू०टी०यू० एवं क्षेत्र के दूसरे अन्य संगठनों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने का फैसला लिया। इस दिशा में कितनी उन्नती हुई, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से इस संदर्भ में अभी तक फैडरेशन को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान के अनुसार फैडरेशन ने अपनी संबद्ध यूनियनों को ११ सितंबर १९७४ को चिली दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। फैडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन की सातवीं कान्फ्रेंस ( जो मास्को में २०-२४ मई १९७५ को होनी है ) में भाग लेने के लिए उप-अध्यक्ष कामरेड परमिल मित्रा का नाम मनोनीत किया।

फैडरेशन ने १४ दिसम्बर १९७४ को कलकत्ता में पदाधिकारियों की वृहत्तर मीटिंग में अपनी दूसरी कान्फ्रेंस बंदी पेरियार में ३१ जनवरी से २ फरवरी १९७५ तक करने का फैसला लिया था जो कामरेड के० आई० राजन की असामयिक मृत्यु के कारण स्थगित करनी पड़ी, फिर भी सी०आई०टी०यू० की तीसरी कान्फ्रेंस के अवसर पर, ११ से १३ मई (१९७५) तक फैडरेशन की मीटिंग उसी स्थान पर हुई।

### (३) बीड़ी उद्योग

हमारी कान्फ्रेंस में शामिल होने वाले डैलीगेटों ने केन्द्र से बीड़ी मजदूरों का एक अखिल भारतीय कन्वेंशन संगठित करने का प्रस्ताव किया था। दिल्ली में कार्यकारी कमेटी ने अपनी मीटिंग में इस मसले पर गौर करने के पश्चात् रीजन (मण्डल) के अनुसार सह-संयोजन करने पर जोर दिया। इसी के मुताबिक, दक्षिण जोन बीड़ी मजदूरों की दूसरी कान्फ्रेंस २६-२७ जनवरी १९७४ को ताल्लीचेरी (केरल)

में हुई जिसमें ४०० डैलीगेटों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के धूलियान (मुर्शिदावाद जिला) और मध्य प्रदेश के दमोह में रीजनल कन्वेंशन हुए। १ अप्रैल १९७४ को विशाखापत्तनम् में इस उद्योग के अगुआ कार्यकर्त्ताओं की एक मीटिंग हुई जिसमें, जनवरी १९७४ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीड़ी और सिगार एक्ट की धाराओं के औचित्य का निर्णय दिये जाने के बावजूद, उसके लागू न किए जाने की स्थिति पर विचार किया। इसमें मई १९७४ में वारंगल (आंध्र) में एक बड़ी मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया गया जो रेलवे हड़ताल के कारण स्थगित करनी पड़ी। बाद को, आंध्र के कामरेडों ने मीटिंग कर सकने में अपनी असामर्थ्यता जाहिर की। बंगलौर के कामरेड भी मीटिंग का इंतजाम नहीं कर सके। अंत में, तामिलनाडु राज्य कमेटी की पहल कदमी पर, वेल्लूर के साथी २ फरवरी १९७५ को इस बड़ी मीटिंग का प्रबंध करने के लिए तैयार हुए। इस कान्फ्रेंस में ८ राज्यों से २१० डैलीगेट आए। उद्घाटन सी०आई०टी०यू० अध्यक्ष कामरेड बी० टी० रणदिवे ने किया। कान्फ्रेंस में कामरेड सी० कन्नन (केरल) के संयोजकत्व में एक संयोजन समिति बनाने का निर्णय लिया। इस संयोजन समिति की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ८ अप्रैल १९७५ को केन्द्रीय श्रम मंत्री से मिला, और बीड़ी एवं सिगार एक्ट के लागू न किए जाने के संदर्भ में एक मेमोरेंडम दिया। इससे पहिले अगस्त १९७४ में मुख्यमंत्री से दक्षिण जोन की यूनियनों का एक और प्रतिनिधि मंडल इन्हीं मांगों को लेकर मिला था।

कर्नाटक में सी०आई०टी०यू० की यूनियनों के नेतृत्व में इस उद्योग के अंतर्गत इस एक्ट को लागू कराने का एक समझौता प्रबंधकों के साथ किया गया। केरल मजदूरों सहित सभी मजदूरों को ८-१/२ प्रतिशत बोनस मिला। फिर भी, यूनियन मजदूरों के पुराने दामों को मनवाने के लिए दबाव डालने में नाकामयाब रही। ४ नवंम्बर १९७४ को पश्चिम बंगाल में बीड़ी मजदूरों का एक शानदार प्रदर्शन निकला और वेतन बढ़ाने, एक्ट लागू कराने एवं अन्य मांगों को लेकर २९ जनवरी १९७५ को एक सफल हड़ताल की गई।

### (४) कोयला उद्योग

पिछले दो साल में कोयला उद्योग में सह-संयोजन की समस्याओं पर सी०आई०टी०यू० सैंटर को काफी ध्यान देना पड़ा है। द्विपक्षीय वेतन समझौता वार्ता कमेटी में हमें एक सीट मिली हुई थी। १९६०

के आधार को लेकर, २४६ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ३२५/-रुपया कम से कम वेतन और १५ रुपया किराया भत्ता हमारे द्वारा तै करने के बाद, एटक और इंटक ने अलग से ऊँची श्रेणी के मजदूरों के लिए कमतर वेतन मांगों पर प्रबंधकों से सौदा कर लिया और विरोध के बावजूद एक समझौता कर डाला। जब इतने पर भी केन्द्रीय सरकार ने इस तथाकथित समझौते को नहीं माना तो एटक और इन्टक का नेतृत्व भी संघर्ष की बात करने के लिए मजबूर हो गया। उन्होंने तीन बार हड़ताल का नोटिस दिया और छद्म कारणों से उन्हें वापस भी ले लिया। अंततः वे मकान किराया-भत्ता, मंहगाई भत्ते में कमी, और भूमिगत भत्ते जैसे सवालों को भी जाने देने के लिए राजी हो गये। सी०आई०टी०यू० ने इन घटिया शर्तों पर समझौता करने से मना कर दिया। हिं. म. स. ने इस समझौते की बाकायदे भर्त्सना भी की। कोयला मजदूरों से संबंधित समझौता-वार्ताओं में निहित मसलों पर विचार करने के लिए हमने जनवरी और अप्रैल १९७४ में कोयला यूनियनों की एक अखिल भारतीय मीटिंग बुलाई। सभी यूनियनों को समय समय पर घटना विकासों की खबर भी दी जाती रही। कामरेड रोबिन चटर्जी को कमेटी के एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। अस्वस्थ होने के कारण कामरेड एम० के० पन्धे को बाद में मनोनीत किया गया।

सी.आई.टी.यू. सैंटर ने सी.एम.ए., बी.सी.सी.एल., एन.सी.डी.सी. और कोयला बोर्ड में कार्यरत क्लर्कों के संगठनों को अपने संघर्ष चलाने में भी मदद दी। उन्हें समझौता वार्ताओं के हर चरण पर सूचनायें दी जाती रहीं। इन सभी संगठनों की एक संयोजन समिति कलकत्ता में बनाई गई जो अब सी. आई. टी. यू. के सहयोग में कार्य कर रही है।

इस उद्योग के महत्व के कारण सी. आई. टी. यू. सैंटर को इसकी ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। अपनी यूनियनों की गतिविधियों को संयोजित करने और स्थानीय एवं रीजनल स्तर पर संयुक्त संघर्ष चलाने के लिए कोई न कोई तरीका निकालना बेहद जरूरी है। इस उद्योग के अंदर हमारे काम के विस्तार की संभावनाएं बेहद ज्यादह हैं और हमें उनका उचित रूप से इस्तेमाल करना चाहिये।

**(५) बिजली उद्योग**

केन्द्रीय सरकार ने बिजली-संस्थानों के लिए वेतनों के निश्चय के लिए एक दिशा निर्देश कमेटी बनायी थी। इस कमेटी में हमें भी

एक सीट मिली। सी. आई. टी. यू. ने कामरेड सुखमय पाल को इस कमेटी के लिये मनोनीत किया। हालांकि कमेटी ने तीस रुपये की अन्तरिम सहायता की सिफारिश की फिर भी बहुत से राज्यों द्वारा इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। हरयाणा और पंजाब में, इन सिफारिशों के लागू कराने की माँग को लेकर की गई हड़तालों के कारण बहुत से बिजली मजदूरों का विक्टिमाइजेशन किया गया। इस मामले में केन्द्रीय सरकार कोई भी कदम उठाने में नाकामयाब रही। चूँकि इस सिलसिले में, इंटक और एटक एक आम संघर्ष के लिये तैयार नहीं थे, इसलिये फरवरी १९७४ के प्रथम सप्ताह में मद्रास में हमें ही एक अखिल भारतीय मीटिंग बुलानी पड़ी। इसमें ऐसे अखिल भारतीय संघर्ष का आधार बनाने का निर्णय हुआ जिसके बिना सरकार नहीं झुक सकती थी। इस मामले पर पुनः ८ अप्रैल १९७४ को विशाखापटनम में विचार विमर्श हुआ। अपर्याप्त तैयारियों के कारण हड़ताल का आह्वान रोकना पड़ा। एटक, हिं.म.स. और सी०आई०टी०यू० के प्रतिनिधियों के संयुक्त फैसले के अनुसार १९ और २० नवंबर को नई दिल्ली में बिजली मजदूरों का एक अखिल भारतीय कन्वेंशन बुलाया गया जिसमें संघर्षों को संयुक्त रूप से आगे ले जाने के लिए एक संयोजन कमेटी बनाई गयी। सी० आई०टी०यू० यूनियनों की ओर से सी०आई०टी०यू० के उप अध्यक्ष कामरेड ई. बालानंदन और कामरेड वी० पी० चिन्तन ने अन्य २० लोगों के साथ कन्वेंशन में हिस्सा लिया। इस कन्वेंशन से पहले हमने अपनी लाइन के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए अपने कामरेडों की एक मीटिंग भी की। मीटिंग में कामरेडों ने सुझाव दिया कि सी०आई०टी०यू० सैंटर को इस उद्योग के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारी गतिविधियाँ बेहतर तरह से निर्देशित एवं संयोजित हो सकें। मार्च १९७५ में हुई दिशा निर्देशक कमेटी की मीटिंग में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि उक्त सवाल पर केन्द्र और राज्य दोनों में से कोई भी किसी अखिल भारतीय समझौते पर पहुंचने का कोई इरादा नहीं रखते। साथ ही संयोजन समिति की अवहेलना करते हुए एटक और इंटक भी अलग से चलने की कोशिश कर रहे थे। तब से आज तक मजदूरों के वेतन की समस्या बर्फ-भण्डार में जमीं पड़ी है और इसीलिए इस उद्योग में एक संयुक्त अखिल भारतीय आंदोलन तैयार करने के लिए कदमों को सोचना पड़ेगा।

# बंदरगाह और गोदी उद्योग

बंदरगाह और गोदी कर्मचारियों के वेतनों में सुधार का सवाल एक लम्बे अरसे से रोका हुआ था। बावजूद इसके कि इस उद्योग में हमारी स्थिति बेहद मजबूत थी, यातायात मंत्रालय ने हमारी उपेक्षा की एवं **एच. एम. एस., इंटक** और **एटक** के नेतृत्व में चलने वाले फैडरेशन से ही संबंध रखा। पश्चिमी बंगाल में हमारी यूनियनों ने अन्य संगठनों के सहयोग से संग्रामी मोर्चे का गठन किया और संयुक्त हड़तालें तथा अन्य प्रकार की गतिविधियां आयोजित की। गोआ और कोचीन में, बावजूद इसके कि सरकार इंटक यूनियनों को बढ़ावा दे रही थी, हमारे नेतृत्व में मजदूरों ने अनेकों संघर्ष किए। हमारी प्रमुख कमजोरियां बम्बई और मद्रास में है जहां हम अभी तक पर्याप्त रास्ता नहीं निकाल सके हैं।इस सवाल पर कार्यकारी कमेटी की सभाओं में भी विचार विमर्श हुआ। मद्रास में राज्य समिति ने कुछ प्रारम्भिक काम शुरू कर दिया है। विशाखापट्नम की जनरल काउंसिल की सभा में सभी बंदरगाहों की स्थिति की समीक्षा की गई और बंदरगाह एवं गोदी मजदूरों एवं मछुआरों का एक अखिल भारतीय कन्वेंशन, कलकत्ता में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार १२ से १४ फरवरी १९७५ तक कन्वैंशन हुआ, जिसमें २७५ प्रतिनिधियों एवं प्रेक्षकों ने भाग लिया। कन्वैंशन का उद्घाटन कामरेड बी० टी० रणदिवे ने किया जबकि खुली सभा को कामरेड ज्योति बसु ने संबोधित किया।

कन्वैंशन में भारत का जल-यातायात मजदूर फैडरेशन बनाने का निर्णय लिया जिसके अध्यक्ष कामरेड गेराल्ड पेरियरा और महासचिव कामरेड नीलमणि घोष बनाए गए। १८ मार्च १९७५ को कन्वेंशन द्वारा स्वीकृत मांगपत्र को प्रचारित-प्रसारित करने के उद्देश्य से, फैडरेशन के आह्वान पर एक अखिल भारतीय मांग-दिवस मनाया गया। मजदूरों की मांगों को मनवाने के लिए फ्रैडरेशन का एक प्रतिनिधि-मंडल यातायात मंत्री से मिला।

सरकार ने, किसी ट्रेड यूनियनों से मनोनीत सदस्य को लिए बिना एक वेतन समिति गठित कर डाली। जो भी हो, तीन 'मान्यता प्राप्त' फैडरेशनों ने इस वेतन समिति के अंतरिम सहायता सुझावों

को मंजूर कर लिया। हालाँकि ये तीनों फैडरेशन वेतन समिति का बहिष्कार करने की बात करती रहीं, परन्तु इन्होंने हमारे साथ एक संयुक्त संघर्ष में शामिल होने की कोई तत्परता नहीं दिखाई। सी. आई. टी. यू. यूनियनों को ही, जहाँ भी हम मजबूत हैं, पर्याप्त वेतन बढ़ोत्तरी के लिए सरकार को बाध्य करने के अभियान को शुरू करने की पहलकदमी करनी पड़ेगी। नई फैडरेशन ने पहले से ही ऐसे संघर्ष के कार्यक्रम को तै कर लिया है।

## स्टील उद्योग

हमारी यूनियनों ने मित्र यूनियनों के साथ मिलकर, स्टील उद्योग की यूनियनों के संघर्षों को सह-संयोजित करने के लिए २६ जुलाई समिति बनाई। समिति ने स्टील मजदूरों की मांगों का एक सामान्य मांग-पत्र बनाया और सभी स्टील केन्द्रों में अभियान को संगठित किया। सितम्बर १९७४ में जमशेदपुर में एक सुसंयोजित कन्वैंशन हुआ जिसमें कामरेड बी० टी० रणदिवे और कामरेड ज्योति बसु ने भाग लिया। कन्वैंशन की सफलता ने हमारे नेतृत्व में स्टील मजदूरों के आंदोलन के विकास को चिन्हित किया। हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी यूनियन ने कमजोर इकाइयों को संगठित करके एवं उन्हें हर मुमकिन सहायता देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बावजूद इसके कि यूनियन ने शासन के आतंक और दमन को देखा है, उसने यह सब किया। द्विपक्षीय वेतन समझौता-वार्ता समिति और स्तरीकरण (स्टैंडर्डाइजेशन) समिति में यूनियन के प्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया और विभिन्न आंदोलनों के जरिए नीचे से लगातार दबाव को बनाए रखा।

इस उद्योग में ध्यान देने योग्य विकास यह है कि टी. आई. एस. सी. ओ. कर्मचारी समिति, जमशेदपुर ने सी. आई. टी. यू. से संबद्ध होने का निर्णय लिया है। नीचे की आम कतारों के मजदूरों के इस संगठन ने एटक और इंटक के प्रभाव क्षेत्र में अपनी अच्छी जगह बना ली है।

द्विपक्षीय वेतन समझौता-वार्ताएं मंद गति से चल रही हैं। स्टील यूनियनें अखिल भारतीय संघर्ष के प्ररिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर संयुक्त आंदोलन चलाने की कोशिशें कर रही हैं। यहाँ तक कि एटक और इंटक का नेतृत्व भी माँगें न माने जाने की हालत में संघर्ष की बातें करने को बाध्य हो गया है।

सी. आई. टी. यू. को द्विपक्षीय अध्ययन दल में शामिल न करने की पुरजोर कोशिशें की गईं। यह दल नवम्बर १९७४ में सोवियत रूस का भ्रमण करके आया। जो भी हो, यह संभव नहीं हो सका और आखिरकार उन्हें हिंदुस्तान स्टील कर्मचारी यूनियन, दुर्गापुर के सह-सचिव कामरेड ज्योति बसु को सम्मिलित करना ही पड़ा। कमेटी की रिपोर्ट उद्योग की सभी यूनियनों और राज्य समितियों में उनकी सूचना और उपयोग के लिए वितरित कर दी गई।

## रबर एवं टायर उद्योग

अखिल भारतीय टायर एवं रबर मज़दूर फैडरेशन, जो जनवरी १९७३ में गठित हुई थी, ने १९७३ में कोई उल्लेखनीय कार्य करके नहीं दिखाया। फैडरेशन की कार्यकारी समिति की सभा १४ दिसम्बर १९७४ से पहले संयोजित नहीं की जा सकी। सभा में न्यूनतम वेतन को निश्चित कराने और सौ फीसदी ले-आफ मुआवजे के लिए, माँग-सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया।

१ और २ अगस्त १९७४ को चिनसुरा (पश्चिम बंगाल) में पूर्वी ज़ोन की एक कन्वेंशन हुई। फैडरेशन के महासचिव ने कन्वेंशन में भाग लिया। **सिएट** के लम्बे संघर्ष के दौरान अध्यक्ष ने बम्बई का दौरा किया। बम्बई यूनियन के कार्यकर्त्ताओं हत्या के मुकदमों में उलझे होने के कारण केन्द्र की गतिविधियों में कुछ दिक्कतें पैदा हो गयीं। हम केन्द्र और स्थानीय यूनियनों और फैडरेशन के नेतृत्वकारी कार्यकर्त्ताओं में नियमित सम्पर्क बनाए रखने में भी कामयाब न रह सके। फैडरेशन की कार्यकारी समिति फैडरेशन की कार्रवाइयों पर विचार करने और कार्यप्रणाली के सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए काँफ्रेंस के दौरान बम्बई में मिल रही है।

## जूट उद्योग

१९७२ में, अखिल भारतीय जूट मजदूर कन्वेंशन यथासंभव जल्दी कराने की योजना, अनेक कठिनाइयों के कारण अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं। किंतु सी. आई. टी. यू. के सचिव कामरेड कमल सरकार, जूट उद्योग की यूनियनों से अपना नियमित संपर्क बनाए हुए हैं। वे नवम्बर १९७४ में कानपुर गए और उन्होंने वहां कार्यकर्त्ताओं की सभाओं को सम्बोधित किया। १९७४ की जूट

मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल जूट मजदूर आँदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। देश-व्यापी संगठन बनाने की संभावनाएं वहां हैं। लेकिन जब तक पश्चिम बंगाल से बाहर की राज्य-समितियां, जिनके राज्यों में जूट फैक्टरियाँ हैं, इस उद्योग की गतिविधियों को सह-संयोजित करने में कुछ और रुचि नहीं लेंगी तब तक उन संभावनाओं को प्राप्त कर सकना असंभव है। वेतन की एकरूपता के सवाल और काम की अन्य स्थितियां जो वर्षों से समाधानित नहीं हो सकी हैं, के लिए केवल एक अखिल भारतीय आंदोलन ही भारत सरकार पर पर्याप्त प्रभाव डालेगा।

## रेयन उद्योग

इस उद्योग की यूनियनें, इस उद्योग की हमारी यूनियनों की कार्रवाइयों को संयोजित करने के लिए कदम उठाने पर जोर दे रही हैं। और क्योंकि हमने लगभग ९ फैक्ट्रियों में काम किया है अतः इस उद्योग में एक अखिल भारतीय आंदोलन बनाने की पहल-कदमी की संभावनायें हैं। सैक्रेटेरिएटने इस सवाल पर विचार किया और १४ दिसम्बर १९७४ को कलकत्ता में अखिल भारतीय सभा आयोजित की। इस सभा ने सी. आई. टी. यू. की गतिविधियों की समीक्षा तो की ही, साथ ही इस उद्योग में आने वाली समस्याओं पर भी विचार किया। विस्कस रेयन मैनुफैक्चरिंग प्रौसैस में विष-प्रयोग पर बैठी आफीशियल समिति की रिपोर्ट को लागू न करने के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। अनुपलब्ध रिपोर्ट के पूरे पाठ को टाइप कराकर सारी यूनियनों में वितरित किया गया और उनसे इस मुद्दे पर आंदोलन करने और दावे पर हस्ताक्षर अभियान चलाने को कहा गया। इस रिपोर्ट को लिखते समय केन्द्र के पास इस अभियान की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

## अन्य उद्योग

१९७१ में कागज उद्योग में काम करने वाले प्रतिनिधियों की एक सभा ने संयोजन का निर्णय लिया और उन्होंने कामरेड रोबिन सेन को संयोजक के रूप में चुना। किन्हीं कारणों से समिति कार्य नहीं कर पाई। ८ अप्रैल १९७४ की विशाखापटनम की जनरल काउंसिल के बाद प्रतिनिधियों की एक दूसरी सभा हुई किंतु पर्याप्त

की बिगड़ी स्थितियों के रहते, समय नहीं निकाल सके।

फार्मास्युटीकल उद्योग में काम करने वाले प्रतिनिधियों की एक सभा एर्नाकुलम् में हुइ जिसमें कामरेड ज्ञान सेन को संयोजक के रूप में चुना किंतु समिति कतई नहीं मिली और इस तरह इस उद्योग में हमारे सह संयोजन से संबंधित अधिक प्रगति नहीं हुई।

साथियो, हमने विभिन्न उद्योगों की अपनी यूनियनों में सह-संयोजन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। कुछ और उद्योगों में भी सह-संयोजन बढ़ाने की मांग उठ रही है। माँग पूरी तरह से उचित है किन्तु जब तक हम ऐसे साथियो की एक टीम नहीं बनाते जो अपनी जिम्मेदारियों को असरदार तरीके से पूरा करने में समर्थ नहीं होंगे यह सह-संयोजन प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। हमारा अनुभव हमें बताता है कि जहाँ-जहां साथियों ने कार्रवाइयों को सह-संयोजित करने में पहलकदमी की है वहां वहां गतिविधियों का विकसित होना संभव हो सका है, कभी कभी हमारे साथियों द्वारा प्रदर्शित स्थानीयता की प्रवृत्तियाँ, एक अखिल भारतीय आंदोलन बनाने के काम में गम्भीर रोड़ा बन जाती है। यदि हमें पूरे देश में उद्योगों के अनुसार अपनी गतिविधियों का जाल फैलाना हैं तो इस कमजोरी पर विजय पानी ही होगी।

सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न सैमिनारों और मीटिंगों में मजदूर वर्ग के सामने आ रही समस्याओं पर अपना अभिमत प्रस्तुत करने के लिए सी०साइ०टी०यू० ने भी भाग लिया। इस सिलसिले में किए काम की संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी जा रही है :—

## सरकारी सैमिनारों और मीटिंगों में हमारी हिस्सेदारी

आई०एल०ओ० और मजदूरों की शिक्षा के लिए बने केन्द्रीय बोर्ड ने २७ अगस्त से दो सप्ताह के लिए बंबई में, जन कल्याण और परिवार नियोजन के बारे में ट्रेड यूनियन के अधिकारियों के लिए एक राष्ट्रीय वर्कशाप संयोजित किया। सी०आई०टी०यू० की ओर से उपप्रधान ने कार्यक्रम में भाग लिया। विचार विमर्श के दौरान उन्होंने सी०आई०टी०यू के दृष्टिकोण को अच्छी तरह से सामने

रखा। सी०आई०टी०यू० की समझ को विस्तार से समझाने वाला एक लिखित पर्चा भी वितरित किया गया।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने नई दिल्ली में १९ और २० अगस्त को औद्योगिक संबंधों पर एक सैमिनार का आयोजन किया जिसमें ९ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया। इस सैमिनार में सी०आई०टी०यू० का प्रतिनिधित्व कामरेड पी० राममूर्ति और कामरेड एम० के० पन्धे ने किया। सैमिनार में उत्पादकता की समस्या के प्रति ट्रेड यूनियन के दृष्टिकोण को व्याख्यायित करने वाला एक वक्तव्य स्वीकृत किया गया।

योजना आयोग की पहलकदमी पर नई दिल्ली में २० जुलाई १९७३ को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की एक मीटिंग बुलाई गई। सी०आई०टी०यू० की ओर से कामरेड बी० टी० रणदिवे और कामरेड पी० राममूर्ति ने विचार-विमर्श में भाग लिया। उन्होंने योजनाओं के चरित्र को जन-विरोधी बताया और बताया कि आज भारत सरकार के द्वारा अपनाई जाती नीतियों के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था का संकट गहराता चला जा रहा है।

नार्वेजियन विकास एजेंसी के सहयोग से आई.एल.ओ. ने १९७३ में बंगलौर और रांची में औद्योगिक संबंधों के ऊपर दो सैमिनार आयोजित किए। इन सैमिनारों में अग्रिम पंक्ति के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, पब्लिक सैक्टर और प्राईवेट सेक्टर—दोनों के प्रबन्ध-प्रतिनिधियों और सरकारी उच्च अफसरों ने भाग लिया। सैक्रेटरिएट के निर्णय के अनुसार ५ और ३ नवम्बर १९७३ को हुई बंगलोर वाली सैमिनार में कामरेड आर० उमानाथ ने हिस्सा लिया। कामरेड एम० के० पन्धे ने १२–१३ नवम्बर को रांची वाली सैमिनार में एक पर्चा पढ़ा। दोनों ही सैमिनारों में हमारे कामरेडों ने सरकार तथा मैनेजमैंट की नीतियों पर तीखा हमला किया और औद्योगिक संबंधों के सभी पहलुओं के बारे में सी०आई०टी०यू० की लाइन का झंडा बुलंद किया।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने ११और १२ जनवरी १९७४ को एक राष्ट्रीय वेतन आयोग के विधान के सवाल पर विचार करने के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सी०आई०टी०यू० का प्रतिनिधित्व कामरेड एम० के० पन्धे ने किया। इस सेमिनार में राष्ट्रीय वेतन आयोग के विचार को

बहुमत से अस्वीकृत कर दिया और १५वीं इंडिया लेबर कान्फ्रेंस द्वारा निर्धारित करने का सुझाव दिया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने १५ से १८ अप्रेल १९७४ तक नई दिल्ली में परिवार नियोजन पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की। सैक्रेटरिएट ने इस विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए कामरेड सुधीन कुमार और कामरेड विरेन राय को मनोनीत किया। कामरेड सुधीन कुमार को स्टीरिंग ग्रुप में मनोनीत किया गया और उन्होंने इस सवाल पर सी०आई०टी०यू० के दृष्टिकोण को बताते हुए एक पर्चा भी पढ़ा।

श्रम मंत्रालय ने १४ और १५ जुलाई १९७३ को कलकत्ता में तीसरी खान-सुरक्षा कान्फ्रेंस को आयोजित किया। पहिले पहल तो हमें सिर्फ एक प्रेक्षक मात्र भेजने का आमंत्रण मिला। यह आमंत्रण भी बिलकुल ऐन वक्त पर मिला। जब हमने इस प्रकार के आचरण का विरोध किया और बहिर्गमन किया तो हमें एक डैलीगेट भेजने एवं एक प्रेक्षक भेजने का निमन्त्रण मिला। कार्यकारी कमेटी के सदस्य कामरेड रबीन चटर्जी ने डैलीगेट की हैसियत से कान्फ्रेंस में भाग लिया।

इस्पात उद्योग के अन्तर्गत सुरक्षा के बारे में बनी एक स्टैंडिंग कमेटी में सी०आई०टी०यू० ने हिस्सा लिया और इसमें जनरल काउंसिल के सदस्य कामरेड दिलीप मजूमदार ने हमारा प्रतिनिधित्व किया। इस उद्योग में सुरक्षा के लिए कुछ नियम बना पाना पहिली बार ही संभव हुआ।

१९७४ केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने कलकत्ता, कानपुर और बंगलौर में एक साथ १८ से २३ नवम्बर १९७४ तक जनसंख्या समस्या पर ३ वर्कशाप कायम किए। हरेक केन्द्र के लिए हमसे ५ प्रतिनिधि मनोनीत करने के लिए कहा गया था। राज्य कमेटियों से सलाह मशविरा करने के पश्चात हम सिर्फ ७ साथियों को ही मनोनीत कर सके। कलकत्ता के लिए कामरेड वीरेन राय, नृसिंह चक्रवर्ती, और विश्वनाथ प्रसाद (बिहार) को मनोनीत किया। कानपुर के लिए कामरेड जगजीत सिंह लायलपुरी (पंजाब), कामरेड घनश्याम शरण सिन्हा (दिल्ली) और का० दुर्गादास शिराली को मनोनीत किया गया, बंगलौर के लिए कामरेड एन० के० उपाध्याय (कर्नाटक) को मनोनीत किया गया। कार्यक्रमों में हमारे कामरेडों ने परिवार नियोजन

कार्यक्रम की आलोचना की और बताया कि यह सफल नहीं हो सकता।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय और आई. एल. ओ. ने मिलकर १८ से २० नवम्बर १९७४ तक मद्रास में 'कम से कम वेतन' पर एक सैमिनार आयोजित किया। इसमें भाग लेने के लिये सैक्रेटरिएट ने कामरेड आर. उमानाथ को मनोनीत किया। कामरेड उमानाथ के प्रस्तुतीकरण को शिरकत करने वाले दूसरे लोगों ने भी एक स्वर से सर्वोत्तम ठहराया। आई० एल० ओ० के अधिकारी श्री पैर्सीटा ने, जो इस सैमिनार के सिलसिले में भारत आये थे, १४ दिसम्बर को भारत में 'कम से कम वेतन' के सवाल पर विचार-विमर्श के लिए सी० आई० टी० यू० के आफिस का दौरा भी किया।

हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ने नई दिल्ली में १८ से २० दिसंबर (१९७४) तक बोनस के ऊपर एक सैमिनार आयोजित किया। सी० आई० टी० यू० की ओर से कामरेड पी० राममूर्ति ने सैमिनार को संबोधित किया।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा बनाई गई मजदूरों की शिक्षा-समीक्षा-समिति को सी० आई० टी० यू० ने एक मैमोरैण्डम भी दिया। इस मैमोरैण्डम में हमने इस समूची योजना की कार्यप्रणाली की आलोचना की और यह भी बताया कि किस प्रकार यह योजना मालिकों और नौकरशाहों की दया पर निर्भर है।

सी०आई०टी०यू० एवं अखिल भारतीय प्लांटेशन वर्कर्स फैडरेशन ने प्लांटेशन संशोधन बिल पर बनी संयुक्त समिति के सामने एक मैमोरेण्डम भी जमा किया। ८ जुलाई १९७४ को अखिल भारतीय प्लांटेशन वर्कर्स फ़ैडरेशन को मौखिक सबूत देने के लिए बुलाया गया। इस सिलसिले में, कामरेड एम० के० पन्धे, के० पद्मनाभन, और कामरेड विमला रणदिवे इस कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए।

हमने भारतीय आचार संहिता (इण्डियन पैनल कोड) के संशोधन बिल पर बनी संयुक्त समिति को भी एक मैमोरेण्डम दिया जिसमें इस बिल की बुनियाद की ही आलोचना की गई। मौखिक सबूत देने के लिए कामरेड एम० के० पन्धे और कामरेड ए० पी० चटर्जी समिति के सामने गये। चेयरमैन के ज्यादतीपूर्ण रवैए के कारण हमारे प्रतिनिधि अपने सबूतों को पूरी तरह से नहीं रख सके। कमेटी के चेयरमैन के इस प्रकार के आचरण के विरुद्ध सी०आई०

टी० यू० के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने राज्य सभा के चेयर मैन के समक्ष विरोध जाहिर किया।

श्री मतो फूलरेणु गुहा की अध्यक्षता में कार्य कर रही महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर कार्य करने वाली कमेटी को सी०आई० टी०यू० द्वारा एक मैमोरेण्डम दिया गया। ३१ जुलाई १९७४ को कामरेड बिमला रणदिवे कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हुई और उन्होंने इस सवाल पर सी०आई०टी०यू० के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया।

विदेशी देन (नियमन) बिल पर बनी संयुक्त समिति को भी सी. आई.टी.यू. ने एक मेमोरंडम दिया। १३ और १४ जनवरी १९७५ को कामरेड एम० के० पन्धे कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने इस बिल के रद्द करने की मांग उठाई।

लोक लेखा समिति के कहने पर, कलकत्ता बंदरगाह आयुक्तों के हिसाब किताब के बारे में कमेटी को सी०आई०टी०यू० ने एक मैमोरेण्डम दिया। ४ मार्च १९७५ को कामरेड एम० के० पन्धे, नीलमणि राय, ए० के० राय गांगुली ने कमेटी के सामने मौखिक सुबूत प्रस्तुत किए।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की केन्द्रीय परिषद की ५ से ७ मार्च तक तथा १५-१६ अप्रैल (१९७५) को बुलाई गई मीटिंग में कामरेड बीरेन राय ने हिस्सा लिया। पहिले कामरेड सुधीन कुमार को मीटिंग के लिए मनोनीत किया गया था किंतु उनके अस्वस्थ हो जाने के कारण, ८ और ९ मार्च (१९७५) को परिषद नियोजन पर हुई ट्रेड यूनियन कमेटी की एक मीटिंग में कामरेड बीरेन राय ने भाग लिया। बाद में यह कमेटी परिवार नियोजन और समाज कल्याण पर एक त्रिपक्षीय कमेटी के रूप में बदल दी गई इस कमेटी की पहली मीटिंग नई दिल्ली में २९ अप्रैल १९७५ को हुई। सैक्रेटेरियट ने कामरेड नृसिंह चक्रवर्ती को कमेटी के लिए मनोनीत किया।

सैमिनारों इत्यादि में हमारी हिस्सेदारी के संबंध में कामरेड पी० राममूर्ति ने विशाखापटनम् जनरल काउंसिल की मीटिंग में निम्नलिखित टिप्पणी की थी :

"हमारे प्रतिनिधियों को मालिकों एवं दूसरे ट्रेड यूनियन केन्द्रों के हरेक तर्क के जबाव के लिए बेहद चौकस और तैयार होना होगा।

कार्यक्रम की आलोचना की और बताया कि यह सफल नहीं हमें इनमें एक राय पर पहुंच जाने के विचार से और अपनी मूल स्थिति पर समझौता करने की गरज से नहीं जाना चाहिए।

हमें अपनी लाइन के दृष्टिकोण को कहने में दो टूक होना पड़ेगा और इस आधार पर कि हम किसी दूसरे पक्ष से बातचीत कर रहे हैं, हमें अपने दृष्टिकोण को मंद नहीं कर डालना चाहिए। हम सैमिनारों में लिखे जाते निबंधों को हमारे कामरेडों को गौर से देखना चाहिए और जैसे ही हम अपनी समझ के विपरीत कोई चीज वहां पाएं तो हमें फौरन ही सही करने के सुझाव देने चाहिए। इस संबंध में होने वाली हमारी कोई भी भूल विरोधियों द्वारा हमारी कतारों में भ्राँतियां फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए. हमें ऐसे सैमिनारों में भाग लेने के लिए उच्चतर कामरेडों को ही भेजना चाहिए, जो विस्तृत तैयारियाँ कर सकें और जो इन सैमिनारों चलताऊ ढंग से व्यवहार न करें। मजदूर वर्ग के सामने आज हमारे सभी मसलों पर सी०आई०टी०यू० की स्थिति को ऊँचा रखने के लिए ये सावधानियां बेहद आवश्यक हैं।'

हमारे प्रतिनिधियों को इन टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि वे अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभा सकें।

## आई०एल०ओ० (अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन) से सी०आई०टी०यू० की शिकायतें

दूसरी कान्फ्रेंस के बाद से अब तक, सी०आई०टी०यू० ने आई० एल० ओ० के सामने आई० एल० ओ० कन्वेंशनों के उल्लंघनों पर चार बार शिकायतें दर्ज कराई हैं।

संगठन की स्वतंत्रता के कन्वेंशन के उल्लंघन के संदर्भ में सी० आई०टी०यू० ने पश्चिम बंगाल में जारी आतंक राज और सी०आई० टी०यू० से संबंध रखने वाली ३०० ट्रेडयूनियनों पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिए जाने के बारे में आई० एल० ओ० को बताया है। १९७५ को पश्चिम बंगाल की जूट हड़ताल के दौरान भी शिकायत दर्ज कराई गई जब कामरेड ज्योति बसु द्वारा संबोधित की जाने वाली एक मीटिंग के लिये इजाजत को सिर्फ इस वजह पर वापस ले लिया गया कि कांग्रेस उसी स्थान पर एक मीटिंग करना चाहती थी (जब कि हालांकि सी०आई०टी०यू० को इजाजत पहिले दी जा चुकी थी।)

सी.आई.टी.यू. ने दूसरी शिकायत रेलवे हड़ताल के दौरान बहुत से रेल मजदूरों के विक्टिमाइजेशन, मजदूरों के परिवारों पर किए गए दमन और आतंक के सवाल को लेकर दर्ज कराई।

एक और शिकायत में सी०आई०टी०यू० ने भारत में आदमी और औरतों के लिये एक समान तनुख्वाह से संबंधित आई.एल.ओ. के कन्वेंशन के नितांत उल्लंघन के बारे में जिक्र किया है। इस शिकायत के बारे में आई०एल०ओ० द्वारा भारत सरकार के साथ बात चीत की गयी। सरकार अब 'समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त' के बिल को लेकर सामने आयी है जिसका विवरण अभी तक नहीं मिल पाया है।

सी०आई०टी०यू०, आई०एल० ओ० का ध्यान कन्वेंशनों के उल्लंघनों की ओर बराबर खींचती रहेगी और इस सिलसिले में देशभर में अभियान चलाती रहेगी जिससे यह सरकार उन कन्वेंशनों को मानने के लिए मजबूर हो जाए जिन्हें इसने अभी तक नहीं माना है।

## कानूनी सहायता कमेटी के काम

रेलवे बोर्ड द्वारा बड़ी संख्या में रेलवे मजदूरों का विक्टिमाइजेशन समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए एक चुनौती था। सी.आई.टी.-यू. ने इस विक्टिमाइजेशन के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया और रेलवे मजदूरों के पक्ष में कानूनी बचाव संगठित किया। इसी के अनुरूप, सी.आई.टी.यू. ने एक कानूनी सहायता कमेटी बनायी और ४ जून १९७५ को कामरेड़ बी.टी. रणदिवे और कामरेड़ पी. राममूर्ति ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें दमनग्रस्त (विक्टिमाइज्ड) रेल मजदूरों के लिए एकजुटता फंड इक्ट्ठा करने की अपील की गयी थी। जल्दी ही सी.आई.टी यू. के केन्द्रीय दफ्तर (कलकता) में लगभग ३० वकीलों की एक मीटिंग हुयी और कामरेड़ ए.पी. चटर्जी के संयोजकत्व में कानूनी सहायता कमेटी बनायी गयी। कामरेड़ बी.टी. रणदिवे और कामरेड बसु इस मीटिंग में उपस्थित थे। इस कानूनी सहायता कमेटी की सहायता के लिए रेलवे के कामरेडों की एक छोटी कमेटी और बनायी गयी। पश्चिम बंगाल में, राज्य कमेटी ने जनता के बीच चंदा इक्ट्ठा किया और सैन्टर को ४०,५०० रुपया दिया, जबकि सी०आई०टी०यू० के पास इक्ट्ठा किया गया कुल चंदा ४५,७५०.४५ रुपया रहा।

कानूनी सहायता कमेटी के कार्य के फलस्वरूप, २०० मजदूरों से संबद्ध २४ केस मजदूरों के पक्ष में तै हुए, जो 'आचरण के रूल' नं. १४ [११] के आधार पर चलाए जा रहे थे। हालांकि अब भी अधिकारियों ने इस बात के खिलाफ फिर अपील भी कर रखी है। कुल मिलाकर हमने ११४ केसों को लड़ा। ८० कैस अब भी सुनवाई की प्रक्रिया में हैं। जनता-राहत-कमेटियों के माध्यम से हम मजदूरों के बीच ६,५०० रुपए का राहत कार्य कर चुके हैं। इसके अलावे, हमने पूर्वी रेलवे के कंचरापाड़ा, सालीमार, खड़गपुर, अडरा और कोयला और राख पर काम करने वाले मजदूरों को भी लगभग ३,३०० रुपए की सहायता प्रदान कर चुके हैं।

कानूनी सहायता कमेटी ने इस दिशा में बेहद काम किया है जैसा कि हमें १ मार्च १९७५ तक किए गए इस कमेटी के काम के नीचे दिए गए ब्योरों से मालूम हो सकता है :–

| केसों के प्रकार | पू.रे.द. | पू.रे. | उ.सी.रे. | योग | मजदूर सं |
|---|---|---|---|---|---|
| नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ [१४(११)] | ५९ | ४६ | २६ | १३१ संख्या | ८१० |
| ,, ,, ,,–[ १४९ ] | १ | ९ | — | १० | ४८९ |
| मीसा के अंतर्गत नजरबंदी के खिलाफ | १५ | ३५ | १३ | ६३ | ६३ |
| ट्रांसफर के खिलाफ | ८ | ९ | — | १७ | ९८ |
| पदावनति के खिलाफ | — | १ | २ | ३ | ३ |
| अनिवार्य रिटायरमैंट के खिलाफ | ५ | २ | — | ७ | ७ |
| डी.आई.आर. के अंतर्गत मुकदमों के खिलाफ | — | ९ | — | ९ | ३८ |
| सरकारी आदेशों की अवमानना के खिलाफ | — | २ | — | २ | ४ |
| कुल योग : | ८८ | ११३ | ४१ | २४२ | १५१२ |

सी० आई० टी० यू० ने कलकत्ता, गुजरात, आंध्र और कोचीन हाई कोर्टों के फैसलों को, रेलवे मजदूरों की कानूनी सहायता से जुड़ी सभी यूनियनों के बीच प्रसारित कराने का भी प्रबंध किया। जिन यूनियनों ने भी सहायता मांगी, उन्हें कानूनी सलाह और अन्य

कानूनी सहायता देना संभव हुआ है। हमने जबलपुर, गोहाटी, पटना नागपुर, कटक को अपने वकीलों को भेजने की भी जिम्मेदारी उठायी। इस कमेटी के द्वारा पीड़ित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी सहायता प्रदान की गयी। हालांकि रेल मजदूरों द्वारा सामना किए गए उत्पीड़न (विक्टिमाइजेशन) के मुकाबले कमेटी द्वारा किया गया यह कार्य बहुत छोटा सा था, फिर भी हमारे इस काम को रेल के आम मजदूर द्वारा सराहा गया। यह उत्पीड़न आज भी जारी है इसलिए इस कमेटी को आगे कुछ और अधिक समय के लिए काम करना पड़ेगा।

डैलीगेटों की सूचना के लिए कानूनी सहायता कोष के लेखे जोखे का ब्योरा इस रिपोर्ट के साथ संबद्ध है।

## नई यूनियनों द्वारा संबद्धता का ग्रहण

एर्नाकुलम की मीटिंग के बाद से अब तक कार्यकारी कमेटी और जनरल काउंसिल ३६,७५८ सदस्यता वाली २०२ यूनियनों को संबद्धता प्रदान कर चुकी हैं, जिनके विवरण यहाँ नीचे दिए जा रहे हैः—

| मीटिंग | यूनियनों की संख्या | सदस्य संख्या |
|---|---|---|
| कार्यकारी कमेटी मीटिंग दिल्ली-अक्तूबर, १९७३ | २४ | ३७१० |
| जनरल काउंसिल मीटिंग विशाखापतनम् अप्रेल १९७४ | ६४ | १८५८१ |
| कार्यकारी कमेटी शिवपुर (हावड़ा), दिसम्बर १९७४ | ११४ | १७४६७ |
| योग | २०२ | ३६७५८ |

चूंकि कुछेक यूनियनों ने अपना सालाना चंदा नहीं भेजा है इस लिए उनकी सदस्य संख्या को निश्चत नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि सदस्यों को मीटिंग के बाद सी०आई०टी०यू० सैंटर को नई यूनियनों के कुछ और संबद्धता-प्रार्थना पत्र

प्राप्त हुए हैं जिन पर तीसरी कान्फ्रेंस के अवसर पर जनरल काउंसिल द्वारा बंबई में विचार विमर्श किया जाएगा।

इस समय के दौरान, सी०आई०टी०यू० को उन यूनियनों की असंबद्धता के बारे में भी विचार करना होगा जो या तो निष्क्रिय हो गई हैं या जिन्होंने नियमित रूप से अपनी संबद्धता फीस जमा नहीं की है। सी०आई०टी०यू० सैंटर ने राज्य कमेटियों को ऐसी यूनियनों की लिस्ट भेजी है। फिर भी उन यूनियनों की असंबद्धता के बारे में सैंटर को कुछ राज्य कमेटीयों से कोई टिप्पणियाँ नहीं प्राप्त हो पाई हैं। शिवपुर कार्यकारी कमेटी ने ११६ यूनियनों को असंबद्ध करने का फैसला लिया और इस कान्फ्रेंस के अधिवेशन से पहले जनरल काउंसिल द्वारा कुछ और यूनियनों के असंबद्ध कर दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा।

जब तक हम संबद्धता की फीस की जमा करने के बारे में सख्ती नहीं दिखाते, कुछेक यूनियनों द्वारा दिखाई गई ढील बढ़ती चली जाएगी। राज्य कमेटियों को भी इस काम में और अधिक दिलचस्पी दिखानी चाहिए जिससे कि यूनियनें इस मामले में चुस्ती से काम लें।

सी०आई०टी०यू० सैक्रेटरिएट ने पश्चिम बंगाल की कुछ यूनियनों, जो दमन और आतंकराज्य के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं—से ली जाने वाली फीस को छोड़ दिया है। फिर भी, उन कुछ यूनियनों के लिए यह सम्मान की बात है जिन्होंने इन सब दमनकारी तौर तरीकों और अन्य बहुत सी परेशानियों के बावजूद फीस को सैंटर के पास जमा किया है।

सन १६७३ के मध्य में सरकार ने सी. आई. टी. यू से १६७२ के लिए सदस्य संख्या की पड़ताल करने के लिए लिस्ट माँगी थी। हमने सितंबर १६७३ में मुख्य श्रम आयुक्त को ६,१२,३२८ सदस्य संख्या वाली २०३१ यूनियनों की लिस्ट प्रदान की। इस सिलसिले में हमने यह भी कहा कि इस तरह से पड़ताल की प्रक्रिया बहुत ही गैर-जनतांत्रिक हैं और इंटक एवं सरकार समर्थक ट्रेड यूनियनों के पक्ष में जाती हैं। इस पत्र में पश्चिम बंगाल में बहुत सी. आई. टी. यू. की यूनियनों के दफ्तरों पर कब्जा कर लिए जाने और जारी आतंक-राज का भी जिक्र किया था।

सी आई टी यू के अतिरिक्त अन्य जिन संगठनों ने लिस्टें दी उनके नाम इस प्रकार हैं: इंटक, यू०टी०यू०सी०, यू०टी०यू०सी० (लेनिन सरणी), भारतीय मजदूर संघ,और राष्ट्रीय श्रम संगठन। एटक और हिं०म०स० ने लिस्टें जमा नहीं कीं और उनके दबाव के कारण सरकार को उनकी पड़ताल के कार्य को छोड़ना पड़ा।

इसी दौरान १९६८ की पड़ताल के परिणामों के आधार पर सरकार ने सभी त्रिपक्षीय कमेटियों का पुनर्गठन कर दिया है और सी०आई०टी०यू० को आज भी उनसे अलग रखा जा रहा है। हमें सिर्फ उन्ही कमेटियों में बुलाया जाता है जहां सरकार द्वारा हमें बाहर रखना मुश्किल हो जाता है। सी०आई०टी०यू० इस प्रकार के पक्ष-पात पूर्ण रवैए के खिलाफ हर स्तर पर संघर्षरत है।

## वियतनाम की ट्रेड यूनियनों की काँग्रेस

वियतनाम की ट्रेड यूनियनों के फैडरेशन की तीसरी राष्ट्रीय कांग्रेस ११-१४ फरवरी १९७४ तक हनोई में हुई। सी०आई०टी० यू० को उसमें शिरकत करने के लिए बुलाया गया। सैक्रेटरिएट ने सी. आई.टी.यू. अध्यक्ष का. बी. टी. रणदिवे को इस कांग्रेस में भाईचारे के डैलीगेट के रूप में उपस्थित होने के लिए मनोनीत किया। इनकी उपस्थिति ने सी:आई.टी.यू. और वियतनाम की ट्रेड यूनियनों के फैडरेशन के बीच मित्रता के बंधनों को और भी मजबूत किया। कांग्रेस के पश्चात् अन्य मित्र डैलीगेटों के संग का०बी० टी० रणदिवे ने कुछ केन्द्रों में दौरे भी किये और उन्होंने वहाँ अमेरिकन साम्राज्य वादियों की बर्बर बम वर्षा द्वारा नष्ट भ्रष्ट की गई अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण में लगी वियतनाम की जनता और वहां के मजदूर वर्ग के अथक प्रयत्नों को महसूस किया। अप्रैल १९७४ में हुई जनरल काउंसिल की मीटिंग में का०बी०टी० रणदिवे ने अपने इस दौरे की एक विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की और जनरल काउंसिल ने वियतनाम में उनके दौरे के दौरान किए गए कार्य के प्रति प्रशंसा व्यक्त की।

## उड़ीसा में सी. आई. टी. यू. राज्य समिति कार्यालय को पूर्व अवस्था में लाने के लिए एकजुटता

३ दिसम्बर १९७४ की आधी रात को कटक स्थित उड़ीसा राज्य सी०आई०टी०यू० कार्यालय में कर्मचारियों के ठेकेदारों ने

आग लगा दी। सारा कार्यालय और रिकार्ड्स जल कर भस्म हो गए। उस समय अन्दर सो रहे कुछ साथी चमत्कारपूर्ण ढंग से ही बच सके। सी०आई०टी०यू० अध्यक्ष ने तत्काल सभी राज्य समितियों को, आफिस को, पूर्व अवस्था में लाने के लिए चंदा देने की अपील की। पश्चिम बंगाल में हो रही राज्य कान्फ्रेंस के उपस्थित प्रतिनिधियों ने एकजुटता फंड की दिशा में १,७०० रुपया भेजा और राजस्थान राज्य कान्फ्रेंस के उपस्थित प्रतिनिधियों ने ५०१ रुपया भेजा। एकजुटता फंड गोआ (१००रु०) और गुजरात (१२१ रु०) राज्यों से भी भेजे गए। उड़ीसा की सी०आई०टी०यू० यूनियनों एवं अन्य मित्र यूनियनों ने भी चंदा दिया। अनुमान किया जाता है कि अब उड़ीसा राज्य समिति जल्दी से जल्दी अपना कार्यालय पुनः स्थापित करने में समर्थ हो सकेगी।

## महिला मजदूरों के बीच काम

दूसरी कान्फ्रेंस के दौरान कुछ समय विशेष रूप से महिला मजदूरों की समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए निर्धारित किया गया। महिला मजदूरों की स्थिति पर कामरेड विमल रणदिवे द्वारा लिखी गयी एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रतिनिधियों में बांटी गयी। कान्फ्रेंस में बोलने वाली कुछ मजदूर महिलाओं ने भी इस समस्या की उपेक्षा की आलोचना की और सी०आई०टी०यू० यूनियनों द्वारा महिला मजदूरों के बीच काम में रुचि लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस विषय पर विचार-विमर्श का सार प्रस्तुत करते हुए कामरेड बी० टी० रणदिवे ने सी०आई०टी०यू० यूनियनों से महिला मजदूरों के बीच गम्भीरतापूर्वक जिम्मेदारी उठाने को कहा।

पश्चिम बंगाल में सी०आई०टी०यू० यूनियनों द्वारा कोयला प्लांटेशनों और बीड़ी और जूट उद्योग की महिला मजदूरों की एक सभा की गई साथ ही १८ और १९ जनवरी १९७४ को बम्बई में महाराष्ट्र की राज्य स्तरीय महिला मजदूर कन्वेंशन आयोजित हुआ जिसमें लगभग २००० महिला मजदूरों ने हिस्सा लिया। भिलाई (मध्य प्रदेश) और राउरकेला (उड़ीसा) में भी महिला मजदूरों के कन्वेन्शन आयोजित हुए।

साथ ही केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की महिला मजदूरों ने महंगाई और जरूरत की चीजों के अभाव के खिलाफ प्रदर्शन किए।

कहना न होगा कि राज्य समितियों द्वारा महिला मजदूरों को संगठित करने और उन्हीं के द्वारा संगठन की अधिकाधिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए प्रशिक्षित करने की दिशा में आगे कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। इस सवाल को खासकर उद्योगों में शीघ्रातिशीघ्र उठाया जाना चाहिए जहां काफी तादात में महिला मजदूर काम कर रही हैं। सी०आई०टी०यू० सैक्रेटेरिएट पहले से ही, महिला मजदूरों की समस्या पर १९७५ के दौरान एक कन्वेंशन या सैमिनार आयोजित करने का निर्णय ले चुका है।

## दि वर्किंग क्लास एवं अन्य सी.आई.टी.यू. पत्रिकायें

दूसरी कान्फ्रेंस में हमने सी०आई०टी०यू० के संविधान में संशोधन किया था और इससे संबद्ध सभी यूनियनों के लिए सी०आई०टी०यू० पत्रिका 'दि वर्किंग क्लास' को मंगवाना अनिवार्य कर दिया था। इसका उद्देश्य यह था कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन के सामने आने वाले मसलों के प्रति सी०आई०टी०यू० की नीतियों और हर राज्य में सी०आई०टी०यू० की गतिविधियों से हरेक यूनियन परिचित रह सके।

इस रिपोर्ट के साथ संलग्न एक वक्तव्य इस पत्रिका के कुल प्रसार की संख्या को हमें दिखाता है। इस वक्तव्य से यह साफ जाहिर हो जाता है कि पिछले दो सालों में इस पत्रिका का प्रसार १००० से ऊपर चला गया है। अप्रेल १९७५ के लिए हमने इसे ४२०० की संख्या में छापा है।

यह एक आम अनुभव रहा है कि जहाँ भी कामरेडों ने प्रयत्न किया है, इस पत्रिका की बिक्री पर्याप्त रूप से बढ़ गई है। भिलाई के कामरेडों ने इसकी बिक्री १३० तक पहुंचा दी है और इससे भी आगे बढ़ाने का वायदा किया है। मुजफ्फरपुर (बिहार) जैसे कमजोर केन्द्र में भी कामरेड इसकी बिक्री १०० तक बढ़ा ले गए हैं। फिर भी, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि अब भी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग केन्द्र हैं जिन्होंने अभी तक इस पत्र की एजेंसी शुरू करने के प्रयत्न नहीं किए है।

यदि हमारे कामरेड इस काम को गंभीरता से करें तो इसका प्रसार ५००० तक पहुंचाना बहुत कठिन नहीं हैं। विशेष रूप से, पढ़े-

लिखे मजदूरों और कर्मचारियों के बीच इसकी बिक्री बढ़ाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। यह एक अच्छी शुरूआत है कि सीoआईo टीoयूo से बाहर के भी बहुत से संगठन 'दि वर्किंग क्लास' को खरीदने लगे हैं। इस पत्रिका में छपे बहुत से लेख ऐसी दूसरी पत्रिकाओं में फिर से प्रकाशित किये जाने लगे हैं जो हमारे मित्र संगठनों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

राज्य कमेटियों द्वारा नियमित रिपोर्ट भेज पाने की असफलता के बारे में शिकायतें कोई नई नहीं हैं। फिर भी, यह स्वीकार करना होगा कि इस दिशा में कुछ राज्य कमेटियों ने कदम उठाने आरंभ किए हैं और दूसरी भी ऐसे कदम उठाएंगी। एक अच्छी बात यह है कि सीoआईoटीoयूo से बाहर की यूनियनों के संवाददाता समय समय पर, इस पत्रिका को रिपोर्टें भेजने लगे हैं।

संपादकीय-मंडल की कार्यविधि को सुधारने की संभावनाएं अभी भी महसूस होती हैं। संपादकीय मंडल के कुछ सदस्य तो, अन्यत्र व्यस्त होने के कारण उपलब्ध ही नहीं हो पाते इसलिए संपादकीय मंडल की कार्यविधि को अधिक सार्थक बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। यह बात भी यहाँ कही जानी चाहिए कि पत्रिका के स्टाफ के, जिनमें कुछ पार्ट टाइम कार्य काने वाले भी शामिल हैं, कामरेडों ने इस पत्रिका को नियमित तौर पर प्रकाशित करने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है।

पश्चिम बंगाल, केरल, आँध्र और महाराष्ट्र की सीo आईo टीo यूo की राज्य कमेटियाँ अपनी भाषाओं में अपनी पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती हैं। महाराष्ट्र राज्य कमेटी को, बीच में लगभग एक साल के लिए अपनी पत्रिका के प्रकाशन को रोकना पड़ गया था, जो अब फिर प्रकाशित होना शुरू हो गई है। श्रमिक आंदोलन (बंगला भाषा) की प्रसार संख्या ४००० है। सीo आईo टीo यूo संदेशम् (मलयाली) कर्मिक लोकम् (तेलगू), और वर्ग-युद्ध (मराठी) की प्रसार संख्या लगभग २००० है।

सीo आईo टीo यूo की पत्रिका हिन्दी में निकले, इस प्रकार की माँग बहुत सी यूनियनों और कामरेडों ने उठाई है। इसके बावजूद सैन्टर इसके प्रकाशन की जिम्मेदारियाँ नहीं ले सका। अब सैन्टर सीo आईo टीo यूo की दिल्ली राज्य कमेटी के सहयोग से

दिल्ली से ही हिन्दी में एक पत्रिका निकालने की संभावनाओं को परख रहा है।

मुद्रण और कागज की मूल्यवृद्धि के कारण 'दि वर्किंग क्लास' को पुरानी कीमत पर प्रकाशित कर पाना मुश्किल है। हालांकि, इन सब कठिनाइयों के बावजूद सैंटर ने अभी तक कीमत को बढ़ाया नहीं है। तथापि, पत्रिका के बढ़ने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए पत्रिका की कीमत को कम से कम ५० पैसे तक बढ़ाना पड़ सकता है।

सी० आई० टी० यू० की इन पत्रिकाओं ने, मजदूरों में सी० आई० टी० यू० की नीतियों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी, इन पत्रिकाओं के उपयोग को ज्यादह से ज्यादह बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए जिससे कि हम अपने पाठकों की बढ़ती आशाओं को पूरा कर सकें।

दूसरी कान्फ्रेंस के बाद हमने १० प्रकाशन किए जिनमें, ७ अंग्रेजी में, २ हिन्दी में और एक बंगला में किया गया। इन प्रकाशनों के शीर्षक इस प्रकार हैं :—

१. दूसरी कान्फ्रेंस के प्रस्ताव और कार्य विवरण (अंग्रेजी)
२. गहराता संकट : उभरते संघर्ष [ नई दिल्ली में ३-५ अक्तूबर (१९७३) को हुई सी०आई०टीयू० की कार्यकारी कमेटी के दस्तावेजों की समीक्षा, (अंग्रेजी) ]
३. लेबर हैन्ड बुक १९७४ (अंग्रेजी)
४. नए जंगी संग्राम की ओर बढ़ो [ (हिन्दी) ७ अप्रैल १९७४ को जनरल काउंसिल में विशाखापत्तनम् में कामरेड बी० टी० रणदिवे का भाषण ]
५. ,, ,, (बंगला)
६. सी०आई०टी०यू० का संविधान (संशोधित संस्करण) (अंग्रेजी)
७. आक्रमण के प्रतिरोध के लिए [ (हिन्दी), ११-१४ दिसंबर १९७४ को हावड़ा में हुई कार्यकारी कमेटी में कामरेड बी० टी० रणदिवे का भाषण ]
८. वेतन नीति के बारे में बनी कमेटी की गुप्त रिपोर्ट की आलोचना [ २८ अगस्त १९७४ को दिल्ली में हुए वेतनजाम के

खिलाफ राष्ट्रीय कन्वेंशन में सी०आई०टी०यू० द्वारा पेश की गई (अंग्रेजी)]

९. विश्व-पूंजीवाद का संकट—बी० टी० रणदिवे (अंग्रेजी)

१०. मुद्रास्फीति और वेतनजाम के खिलाफ — बी० टी० रणदिवे (अंग्रेजी)

इनमें से अधिकाँश प्रकाशन बिके हैं। लेबर हैण्डबुक तो सी० आई०टी०यू० से बाहर की यूनियनों तक में लोकप्रिय हुई। पहिला संस्करण कतई बिक गया है और दूसरा छप रहा है।

पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र और दिल्ली राज्य कमेटियों ने अपनी बोलचाल की भाषाओं में छोटी छोटी किताबें छापी हैं और उनकी बिक्री भी संयोजित की है। सी०आई० टी०यू० के दस्तावेज मुख्यतः अंग्रेजी में ही प्रकाशित होते हैं और उन्हें मजदूरों के वृहत्तर हिस्सों में लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। आशा की जाती है कि राज्य कमेटियाँ इस सिलसिले में अधिक ध्यान देंगी जिससे कि ज्यादा देर किए बिना इस संदर्भ में अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकें।

# "दि वर्किंग क्लास" के वितरण का ब्यौरा
## (१९७३ से १९७५ तक)

| राज्य | मार्च १९७३ भेजी गई कुल प्रतियां | मार्च १९७४ भेजी गई कुल प्रतियां | मार्च १९७५ भेजी गई कुल प्रतियां |
|---|---|---|---|
| आसाम | ५९ | १०७ | १५७ |
| अण्डमान | १ | १ | २ |
| आंध्र प्रदेश | ११९ | १९७ | १६८ |
| बिहार | २१२ | २५३ | २१८ |
| गुजरात | ५ | ८ | २३ |
| गोआ | १५ | १ | १६ |
| हरियाणा | १७ | ९ | ९ |
| हिमाचल प्रदेश | ३ | १८ | २६ |
| जम्मू-कश्मीर | १ | — | ३ |
| कर्नाटक | १५८ | १३७ | १८२ |
| केरल | ११९ | १४१ | ४८० |
| महाराष्ट्र | २१६ | २३० | २७५ |
| मध्य प्रदेश | १४६ | १६९ | २१७ |
| नई दिल्ली | ११० | ७० | ९७ |
| उड़ीसा | ५९ | ३० | ८७ |
| पाँडिचेरी | १ | १ | २ |
| पंजाब | ९७ | १३९ | १६१ |
| राजस्थान | २५ | १७ | २१ |
| तमिलनाडु | २९१ | २७६ | ३३२ |
| त्रिपुरा | १ | २ | ३ |
| उत्तर प्रदेश | ६२ | ८३ | ७० |
| पश्चिम बंगाल | ७३१ | ६८९ | ८९२ |
| योग | २,४४९ | २,५८० | ३,४४१ |
| नकद विक्रय | १५३ | १८१ | ३७८ |
| सद्भावना प्रतियां | १०४ | ११७ | १२० |
| विदेश | ३५ | ५२ | ३२ |
| कुल योग | २,७४१ | २,९३० | ३,९७१ |

# दमनग्रस्त रेलवे मजदूरों

## २६ मई १९७४ से ३१ मार्च १९७५ तक के

प्राप्ति (रुपयों में)

| | | |
|---|---|---|
| जिनसे अनुदान प्राप्त हुए | | ४५,७५०.४५ |
| १. प० बंगाल राज्य समिति सीटू | ४०,५००.०० | |
| २. एन.सी.सी.आर.एस. संत्रगाची | ५००.०० | |
| ३. रेलवेमैंस की यूनाइटेड कमेटी | ५००.०० | |
| ४. वर्कशाप स्टाफ कमेटी, खड़गपुर | ५००.०० | |
| ५. एस.ई. रेलवे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, आद्रा | ५००.०० | |
| ६. एन.एफ. रेलवे, गौहाटी | २००.०० | |
| ७. दार्जलिंग जिला चिया कमान मजदूर यूनियन | २२८.४५ | |
| ८. कोयला श्रमिक संघ, सुरगुजा | १०२.०० | |
| ९. ए.बी.टी.ए. कालिज कलकत्ता | १३५.०० | |
| १०. १२ जुलाई समिति | १००.०० | |
| ११. त्रिपुरा राज्य समिति सीटू | ५७७.०० | |
| १२. त्रिपुरा स्टूडैण्ट्स फैडरेशन | २००.०० | |
| १३. उड़ीसा स्टूडैण्ट्स फैडरेशन | २००.०० | |
| १४. प० बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, प० बंगाल | ३३०.०० | |
| १५. कलिंग ट्यूब एण्ड एलाइड कंसर्न कर्मचारी यूनियन | १२६.०० | |
| १६. स्टाफ, सैंट्रल आफिस, सीटू | ५०.०० | |
| १७. दक्षिणी रेलवे, सी.एल. यूनियन्स, सेक्लासपुर | १००.०० | |
| १८. एल.आर.एस.ए., माल्दा, प० बंगाल | १५०.०० | |
| ९. अन्य..... | ७५३.०० | |
| | ४५,७५०.४५ | |
| | | ४५,७५०.४५ |

## का कानूनी सहायता कोष

**समय का प्राप्ति और भुगतान का ब्यौरा**

| | | भुगतान (रुपयों में) |
|---|---|---|
| कानूनी खर्च | | |
| रेलवे मजदूरों को सहायता | | १८,११७.०० |
| इंडियन रेलवे कोल एण्ड ऐश हैंडलिंग मजदूर यूनियन | | |
| बंडेल, हुगली, प० बंगाल | ३००.०० | |
| खड़गपुर के दमनग्रस्त रेलवे मजदूर | ५००.०० | |
| रानाघाट के दमनग्रस्त रेलवे मजदूर | ५००.०० | |
| शालीमार के दमनग्रस्त रेलवे मजदूर | ५००.०० | |
| इंडियन रेलवे कोल एण्ड ऐश हैंडलिंग यूनियन | ५००.०० | २३००.०० |
| आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, एस.ई. रेलवे ज़ोन आंध्रा के लिये कानूनी सहायता | | १०००.०० |
| **पीपुल्स रिलीफ कमेटी को भुगतान** | | |
| पीपुल्स रिलीफ कमेटी | ५०००.०० | |
| पीपुल्स रिलीफ कमेटी खड़गपुर और कंचरापारा में सहायता केन्द्र-संगठन के लिये | १५००.०० | ६५००.०० |
| स्टेशनरी | | ६४०८,७४ |
| यात्रा व्यय | | १६२८.६० |
| अन्य व्यय | | ३१४.३५ |
| डाक व्यय | | १५२.०५ |
| टाइपिंग व्यय | | १०८१.६५ |
| दो शतरंजों का मूल्य | | १०५.०० |
| एक स्टील ट्रंक का मूल्य | | ३४.०० |
| टाइप राइटर मरम्मत | | २०० ०० |
| हस्तगत राशि | १६५८.७६ | |
| सीटू के पास राशि | ६२५०.०० | ७९०८ ७६ |
| | | ४५,७५०.४५ |

# 'दि वर्किंग क्लास'

## समय समापन पर प्राप्ति और भुगतान का ब्यौरा, ३१ दिसम्बर १९७३ एवं १९७४

| प्राप्ति (रुपयों में) | | १९७३ | १९७४ |
|---|---|---|---|
| प्रति ओपिनिंग बैलेंस | | | |
| हस्तगत राशि | १५.२१ | | |
| बैंक में राशि | १७९० ३८ | १८०५.५९ | |
| हस्तगत राशि | २४७.२७ | | |
| बैंक में राशि | ९४५.१५ | | ११९२.४२ |
| प्राप्त चन्दा | | १०१८०.९५ | १२६६७.१४ |
| लोन | | ११०००.०० | ३००.०० |
| | | १२९८६.५४ | १४१५९.५६ |

| भुगतान (रुपयों में) | | १९७३ | १९७४ |
|---|---|---|---|
| छपाई व्यय | | ५०५१.३१ | ६०७०.८६ |
| बाइंडिंग और पैकिंग | | ७२९.०० | ७५०.४० |
| स्टेशनरी | | ११९.७० | १६२.८२ |
| रेलवे पार्सल व्यय | | ७२.९७ | ५९.१६ |
| डाक व्यय | | ७२०.२० | ८९७.१३ |
| न्यूज प्रिंट | | ४९३०.२५ | ३९५३.०० |
| यात्रा व्यय | | २७.५० | ४३.८५ |
| कुली भाड़ा | | ६८.३१ | ७८.४९ |
| अतिरिक्त व्यय | | ५८.८८ | ९२.१० |
| बैंक व्यय | | १६.०० | २२.०० |
| हस्तगत राशि | २४७.४९ | | |
| बैंक में राशि | ९४५.१५ | ११९२.४२ | |
| हस्तगत राशि | २०.१२ | | |
| बैंक में राशि | २००९.६३ | | २०२९.७५ |
| | | १२९८६.५४ | १४१५९.५६ |

एम० के० पन्धे द्वारा सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए
१७२, लेनिन सरणी, कलकत्ता-७०००१२ से प्रकाशित तथा
प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स, १, लारेंस रोड, दिल्ली-३५ से मुद्रित